



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 1973/जेष्ठ 5, 1895
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 1973/Jyaistha 5, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आवेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1973

विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की
तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्थक घोषित करता है।

[सं. ग. सं.नं. स./87/71(50)]

ORDER

New Delhi, the 9th April, 1973

का. आ. 1463.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया
है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए
निर्वाचन के लिए 87 बादुरिया निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले
उम्मीदवार श्री हरेन्द्र मुखर्जी ग्राम व पो. आ. बादुरिया, जिला
24-परगना, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन
व्ययों का कंई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने
पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कंई कारण अथवा स्पष्टीकरण
नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि
उसके पास इस असफलता के लिए कंई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य
नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसार में
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री हरेन्द्र मुखर्जी को
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा

S.O. 1463.—Whereas the Election Commission is satisfied
that Shri Harendra Mukherjee, Village and P.O. Badurai,
district 24-Parganas, West Bengal, a contesting candidate for
election to the West Bengal Legislative Assembly from 87-
Baduria constituency held in March, 1971 has failed to
lodge an account of his election expenses as required by the
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made
thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice
has not given any reason or explanation for the failure and
the Election Commission is further satisfied that he has no
good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri
Harendra Mukherjee to be disqualified for being chosen as,

(1907)

and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/87/71(50)]

आदेश

का. आ. 1464.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 107 ब्रिशनपुर पश्चिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमिया कान्ति मंडल, ग्राम सुलतानगुंजे, पो. आ. गोदोलाहट, कृष्णपुर, जिला 24-परगना (पश्चिम बंगाल), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपना इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अमिया कान्ति मंडल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प. बं. नि. व. स./107/71(51)]

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1973

S.O. 1464.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amiya Kanti Mandal, Village Sultangunge, P.O. Gotolahat, Krishnapur, district 24-Parganas (West Bengal), a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 107-Bishnupur West constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amiya Kanti Mandal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/107/71(51)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

का. आ. 1465.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 98 बारुइपुर (अजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जितेन हलदर, ग्राम व पो. आ. चम्पाहाटी, जिला 24-परगना, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपना इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जितेन हलदर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प. बं. नि. व. स./98/71(55)]

ORDER

New Delhi, the 12th April, 1973

S.O. 1465.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jiten Halder, Village and P.O. Champahati, district 24-Parganas, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 98-Baruipur (SC) constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jiten Halder to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/98/71(55)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

का. आ. 1466.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए 108 ब्रिशनपुर पूर्व (अजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री द्विजबहार मंडल, ग्राम गांधाबादली पो. आ. ब्रिशनपुर, जिला 24-परगना (पश्चिम बंगाल), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपना इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री द्विजबहार मंडल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प. बं. नि. व. स./108/71(53)]

ORDER

New Delhi, the 12th April, 1973

S.O. 1466.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dwija Bar Mandal, Village Gandhabaduli, P.O. Bishnupur, district 24-Parganas (West Bengal), a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 108-Bishnupur East (SC) constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dwija Bar Mandal to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/108/71(53)]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

आदेश

का. आ. 1467.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए 113 कुलपी (अजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कार्तिक मंडल, ग्राम हंसुरी, पो. आ. हंसुरी, जिला 24-परगना (पश्चिम बंगाल), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कार्तिक मंडल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है ।

[सं. प. बं.-वि.स./113/71(52)]

New Delhi, the 12th April, 1973

ORDER

S.O. 1467.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kartick Mondal, Village Hansuri, P.O. Hansuri, district 24-Parganas (West Bengal), a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 113-Kulpi (SC) constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kartick Mondal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/113/71(52)]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

आदेश

का. आ. 1468.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 117 सागर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री म. अब्दुस सत्तार सहा, ग्राम व पो. आ. मन्दिर ताला, जिला 24 परगना (पश्चिम बंगाल), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री म. अब्दुस सत्तार सहा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है ।

[सं. प. बं. वि. स./117/71(56)]

New Delhi, the 12th April, 1973

ORDER

S.O. 1468.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Md. Abdus Sattar Sha, Village and Post office Mandirtala, district 24-Parganas, (West Bengal), a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 117-Sagar constituency held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder.

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Md. Abdus Sattar Sha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/117/71(56)]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

आदेश

का. आ. 1469.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 283 नदनघाट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मण्डी शंकर ग्राम व पो. आ. सिमलोन, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मण्डी शंकर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है ।

[सं. प. बं.-वि. स./263/72(54)]

New Delhi, the 12th April, 1973

ORDER

S.O. 1469.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mandi Sankar, Village and P.O. Simlon, district Burdwan (West Bengal), a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 263-Nadanga constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mandi Sankar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/263/72(54)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1973

का. आ. 1470.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 55 दोमकल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मँदुल इस्लाम खोंडाकर, ग्राम शिवनगर, पो. आ. शिवनगर इयासकरपुर जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मँदुल इस्लाम खोंडाकर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. प. बं.-वि. स./55/71(57)]

New Delhi, the 19th April, 1973

ORDER

S.O. 1470.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Maidul Islam Khondaker, Village Shibnagar, P.O. Shibnagar, Iaskarpur, District Murshidabad, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 55-Domkal constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Maidul Islam Khondaker to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/55/71(57)]

आदेश

का. आ. 1471.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 55 दोमकल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुनिल ब्रह्मचारी, ग्राम कटकोपुरा, पो. आ. रायपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण

नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री सुनिल ब्रह्मचारी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. प. बं.-वि. स./55/71(58)]

ORDER

S.O. 1471.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sunil Brahmachary, Village Katakopra, P.O. Raipur, district Murshidabad, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 55-Domkal constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sunil Brahmachary to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/55/71(58)]

आदेश

का. आ. 1472.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 97 जयनगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुनिल भट्टाचार्य, ग्राम पूबो बिशनपुर, पो. आ. साउथ बिशनपुर, पी. एस. मन्दिर बाजार, जि. प. 24 परगना, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री सुनिल भट्टाचार्य को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. प. बं.-वि. स./97/72-उप(59)]

ORDER

S.O. 1472.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sunil Bhattacharya, Village Purba Bishnupur, P.O. South Bishnupur, P. S. Mandirbazar, district 24-Parganas, West Bengal, a contesting candidate for bye-election to the West Bengal Legislative Assembly from 97-Joynagar constituency, held in June, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sunil Bhattacharya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/97/72-Dye(59)]

आदेश

का. आ. 1473.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 243 सोनामुखी (अज) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मदन लोहार, ग्राम मेथाना, पो. आ. बांकीसोल, जिला बांकुरा (पश्चिम बंगाल), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मदन लोहार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. प. बं. वि. स./243/72(60)]

ए. एन. सेन, सचिव

ORDER

S.O. 1473.—Whereas the Election Commission is satisfied that Madan Lohar, Village Methana, P.O. Bankisol, District Bankura (West Bengal) a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 243-Sona-mukhi (SC) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or jurisdiction for such failure.

Now, Therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Madan Lohar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/243/72(60)]

By Order,
A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1973

का. आ. 1474.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 232-भवानी पेट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तुकाराम सीताराम लोनारे 315-गुरुवार पेट, पूना-2 (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री तुकाराम सीताराम लोनारे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. महा-वि. स./232/72(18)]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1973

S.O. 1474.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tukaram Sitaram Lonare, 315 Guruwar Peth, Poona-2 (Maharashtra), a contesting candidate for the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 232-Bhavani Peth Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tukaram Sitaram Lonare to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/232/72(18)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1973

का. आ. 1475.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 172 बिड़ला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रंगलाल, ग्राम व पो. आ. पालामनी, जिला जोधपुर राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रंगलाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. राज. वि. स./172/72(1)]

New Delhi, the 3rd May, 1973

ORDER

S.O. 1475.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rang Lal, village and Post—Palasani, District Jodhpur, Rajasthan, a contesting candidate for the general election to the Rajasthan Legislative Assembly from 172—Bilara Assembly Constituency, held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder:

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares that said Shri Rang Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/172/72(1)]
By Order,

आदेश

का. आ. 1476.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 175-फलोदी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भगवानदास, ग्राम व पो. आ. बाप, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वांछित करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री भगवानदास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. राज. वि. स./175/72(3)]

ORDER

S.O. 1476.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagwan Das, Village and Post Bap, Tehsil Phalodi, District Jodhpur, Rajasthan, a contesting candidate for General election to the Rajasthan Legislative Assembly from 175-Phalodi Constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has not good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagwan Das to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/175/72(3)]

आदेश

का. आ. 1477.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 175-फलोदी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बल्ली खां, सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वांछित करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बल्ली खां को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. राज. वि. स./175/72(2)]

बी. एन. भारद्वाज, सचिव

ORDER

S.O. 1477.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Valli Khan, Inside Sivanchi Gate, Jodhpur, Rajasthan, a contesting candidate for General election to the Rajasthan Legislative Assembly from 175-Phalodi Constituency held in March, 1972, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Valli Khan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/175/72(2)]

B. N. BHARDWAJ, Secy.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1973.

आपक

का. आ. 1478.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, विहित प्राणिकारी द्वारा आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

संस्था

किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, पूना।

[सं. 332/फा. सं. 203/9/73-आयकर अधिनियम 2]

टी. पी. भट्टनवाला, सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 21st April, 1973

INCOME TAX

S.O. 1478.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

**KING EDWARD MEMORIAL RESEARCH CENTRE,
POONA.**

[No. 332(F. No. 203/9/73-ITA. II)
T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.]

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1973

क्र. आ. 1479.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री बी. डी. गार्वरे, अध्यक्ष, गार्वरे ग्रुप आफ कन्सर्न्स चन्द्र मुखी, नारीमन प्वाएंट, बम्बई-1 को 7 मई, 1973 से आरम्भ होने वाले 2 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. फा. 9-2/15/72-बी. ओ. 1 (1)]

(Department of Banking)

New Delhi, the 1st May, 1973

S.O. 1479.—In Pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government hereby appoints Shri B. D. Garware, Chairman of Garware Group of Concerns, Chander Mukhi, Nariman Point, Bombay-1, as the Vice-Chairman of the State Bank of India for a period of two years commencing on 7th May, 1973.

[No. F. 9-2/15/72-BO. I (II)]

क्र. आ. 1480.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (1955 का 23) की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत के रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्वारा निम्नीलिखित व्यक्तियों को भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक, 7 मई, 1973 से नाम निर्देशित करती है :—

श्री एस. एन. सैन के स्थान पर.—श्री बी. डी. गार्वरे अध्यक्ष, गार्वरे ग्रुप आफ कन्सर्न्स चन्द्र मुखी नारीमन प्वाएंट बम्बई-1

श्री पी. व. मेनन के स्थान पर.—श्री अजीत कुमार बिसवास अर्थशास्त्र के प्राचार्य दिल्ली स्कूल आफ इकॉनॉमिक्स डी 13/4 मॉडल टाउन दिल्ली-9

श्री जी. के. भात के स्थान पर.—डा. एस. एम. पाटिल अध्यक्ष एवं प्रबंधनिदेशक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर-31

श्री डी. सी. खन्ना के स्थान पर.—डा. सदाशिव मिश्रा अर्थशास्त्र के प्राचार्य रवेनशा कालेज कटक

[सं. 9-2/15/72-बीओ 1 (2)]

S.O. 1480.—In pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons to be Directors of the Central Board of the State Bank of India, with effect from 7th May, 1973 :—

1. Shri B. D. Garware,
Vice Shri S. N. Sen.
chairman,
Garware Group of Concerns.
Chander Mukhi,
Nariman Point,
BOMBAY-1.

2. Shri Ajit Kumar Biswas,
Vice Shri P. A. Menon
Professor of Economics,
Delhi School of Economics,
D 13/4, Model Town,
Delhi-9.

3. Dr. S. M. Patil,
Vice Shri G. K. Bhagat
Chairman & Managing Director,
Hindustan Machine Tools Ltd.
Bangalore-31.

4. Dr. Sadasiv Misra,
Vice Shri D. C. Khanna.
Professor of Economics,
Ravenshaw College,

[No. F. 9-2/15/72-BO. I (II)]

क्र. आ. 1481.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्वारा निम्नीलिखित व्यक्तियों को क्रमशः अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, हवराबाद, कानपुर, मद्रास, नई दिल्ली और पटना के स्थानीय बोर्डों के सदस्य के रूप में, 7 मई, 1973 से नाम निर्देशित करती है :—

अहमदाबाद स्थानीय बोर्ड

1. श्री सैम्यूल पाल, निवेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेज-
मेंट वस्तरापुर अहमदाबाद-15

2. उपाचार्य जितेन्द्रा एल. दालीकिया, रीडर इन इकॉनॉमिक्स एवं मुख्य यूनिवर्सिटी रोजगार ब्यूरो गुजरात यूनिवर्सिटी 6-साबरकण्ठ सोसाइटी निकट आल इंडिया रीडियो अहमदाबाद-9

3. श्री. बी. एस. वोला, सरपंच, ग्राम पंचायत दरबंगा, पो. आ. गगड़ तालुका डालका जिला अहमदाबाद

4. श्री रीतलाल एम. अंधीरिया भांग निदेशक वि. गुजरात एसी-कलचरल यूनिवर्सिटी जूनागढ़ कैम्पस, जूनागढ़

भोपाल स्थानीय बोर्ड

1. डा. दया शंकर नाग प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, विशारद स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान यूनिवर्सिटी आफ जबलपुर 299 नपीयर टाउन जबलपुर

2. श्री रामाकान्त विश्वनाथ खोड़े निदेशक म. प्र. राज्य सहाकारिता बैंक डिगगांज रोड, खरगारन (पश्चिम निमार) मध्य प्रदेश

3. श्री रवेनाथ चौरा सधस्य लघु कृषक विकास आभिकरण ग्राम रिहोरा, ग्राम पिपला, नरैनवार जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

4. श्री गनेश प्रसाद वर्मा स्वत्वधारी खजुराहो आर्ट्स स्क्वायर
जिला छत्तरपुर मध्य प्रदेश
5. श्री प्रेम स्वरूप कलानी, निदेशक इबोर लैंड एंज फुर्नेन्स
प्रा. लि. कमल विला, 11, टुंगगंज रोड, इंदौर

वर्गस्थ स्थानीय बोर्ड

1. श्री ए. आर. भट, मैम्बर नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल
(रा. वि. परि.) 1218, सदाशिव पेठ, पूना-30
2. श्री नीलकण्ठ ए. कल्याणी प्रबंध निदेशक भारत फोर्ज कंपनी
लिमिटेड 49, श्री शिवाजी कॉऑपरेटिव हाउसिंग
सोसाइटी, पूना-16
3. श्री बी. आर. बखाले, प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र हाइवेड सीड
कार्पोरेशन जलना, जिला औरंगाबाद
4. श्री अनिल कुमार तमाने शुक्रावली, नागपुर

कलकत्ता स्थानीय बोर्ड

1. श्री सुकुमार राय निदेशक, दि शिलांग हाइड्रो-इलेक्ट्रिक
कम्पनी लिमिटेड 57, लेंसहाउन रोड कलकत्ता-25
2. श्री डी. एन. लोहरी भागीदार, पालनीर इंजीनियरिंग कर्पो-
रेशन 329, जोधपुर पार्क, कलकत्ता-31
3. डा. बी. एन. साहू उड़ीसा यूनिवर्सिटी आफ कृषि एवं
प्रोड्यूसिंगकी युनिट 8, कृषि बस्ती क्वाटर सं. 4, टाइप 4
भुवनेश्वर, उड़ीसा
4. श्री आस्टीसन जी मोमिन, अर्थशास्त्र प्राचार्य राजकीय महा-
विद्यालय अपर चांदभारी तरा गारो हिल्स, मेघालय

हैदराबाद स्थानीय बोर्ड

1. डा. एस. भगवन्धन, अध्यक्ष, श्री सध्या इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा.)
लिमिटेड 425, राजमहल एक्सटेंशन बंगलोर-8
2. श्री ई. बी. वी. राधाबाईया प्रबंध निदेशक विजय स्पिनिंग
मिल्स लिमिटेड विजयवाड़ा
3. श्री ए. वी. प्रताप रैड्डी 98, आवर्ध नगर हैदराबाद-4
4. श्री के. आर. चौधरी, प्रबंध निदेशक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर
एवं इन्वैस्टमेंट कम्पनी, प्रीती 21512, अमीरपेट, हैदराबाद
5. श्री ए. हनुमंथा राय, अवैतनिक बेंच मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग
बेंच मजिस्ट्रेट का न्यायालय यादवा स्ट्रीट पुराना गुंटूर

कानपुर स्थानीय बोर्ड

1. डा. बलजीत सिंह अर्थशास्त्र प्राचार्य एवं शाखाध्यक्ष आफ दी
कला संकाय लखनऊ यूनिवर्सिटी 74, बाइसाह बाग
लखनऊ
2. श्री एन. एल. खन्ना निदेशक कंसुल एण्ड कम्पनी (प्राइ.)
लि. 8/215, आर्यनगर कानपुर
3. डा. एस. के. आर. भंडारी ज्येष्ठ प्राचार्य वाणिज्य व्यापार प्रबंध
संकाय बनारस हिन्दू, यूनिवर्सिटी सी-2-1, जोधपुर
कालोनी वाराणसी
4. श्री रामप्रसाद तम्ता प्रीजिडेंट म्युनिसिपल बोर्ड हरी निवास
अलमोड़ा
5. प्राचार्य एस. एस. खान प्रधानाचार्य, अर्थशास्त्र विभाग एवं
शाखाध्यक्ष समाज विज्ञान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
अलीगढ़

मद्रास स्थानीय बोर्ड

1. श्री के. एस. मेनन मापीलायी, प्रबंध निदेशक मद्रास रबल
फैक्टरी 71, जी. एन. चैटी रोड, मद्रास-17
2. श्री के. एस. करयलार निदेशक द्राघनकार रेयन लिमिटेड
थाइकोड, त्रिवेन्द्रम ।
3. श्री ई. गोपालाकृष्णन, इंजीनियर परामर्शदाता, आनन्द
आराम हाक-कोटकर, एस. के. बाया मंगलोर पी. आर्डी.
एन.-574152.
4. श्री एस. आर. काईवार निदेशक, शाशास्त्री पेपर एंज बोर्ड लि.
मेरु 12, फ्रेन्ट सेक्रेट रोड गांधी नगर, मद्रास-60020
5. श्री के. एस. सुब्रह्मण्यम गौंडार प्रीजिडेंट तिरुचैनगोड सर-
कारी विपणन सोसाइटी लि. लक्ष्मी सदीनम कॉंगनपुर
(पोस्ट) संकारी तालुक जिला-सालम

नई दिल्ली स्थानीय बोर्ड

1. कोटन जय सिंह राठौर अध्यक्ष, अजमेर सेंट्रल सहकारी
बैंक गांव और डाकखाना-पारा, जिला अजमेर
2. श्रीमती विद्या स्टोक्स पार्टनर मैसर्स स्टोक्स इंडस्ट्रीस
प्रमेलु डक-धानेघर शिमला हिल्स
3. डा. बी. एम. भाटिया मुख्याध्यापक हिन्दू कालेज 3, इंपी-
रियल एन्यु यूनिवर्सिटी इन्कलेव, दिल्ली यूनिवर्सिटी
3. श्री क्यू. एच. फरूक, ज्येष्ठ प्रधानाचार्य एवं वाणिज्य शाखा-
ध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कामर मीजल दिगी
रोड, अलीगढ़

पटना स्थानीय बोर्ड

1. श्री रंचोर प्रसाद अध्यक्ष हवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन 3,
पाटलीपुत्रा कोलोनी पटना
2. श्री नागिन बी पारिख प्रबंध निदेशक उत्कल ओटोमोबाइल्स
प्रा. लि. मैन रोड, बिस्तापुर जमशेदपुर
3. श्री के. एस. वी. रमन, 400 कौनाल बोरिंग रोड, पटना-1
4. श्री नागेन्द्रा नारायण सिन्हा सभापति, भारतीय समाज कल्याण
परिषद् अन्ने बसन्त रोड, पटना-4
5. स्वामी युक्तानंदा उप सभापति रामाकृष्ण मिशन आश्रम
मोराबंदी संची-83008 ।

[सं. फा. 9-2(15)/72-बीओ 1 (3)]

डी. एन. घोष, संयुक्त सचिव

S.O. 1481.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 21 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons to be members of the Ahmedabad, Bhopal, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, New Delhi and Patna Local Boards respectively, with effect from 7th May, 1973 :-

AHMEDABAD LOCAL BOARD

1. Shri Samuel Paul,
Director,
Indian Institute of Management,
Vastrapur,
Ahmedabad-15.
2. Prof. Jitendra L. Dholaia,
Reader in Economics & Chief,
University Employment Bureau,
Gujarat University,
6. Sabarkunj Society,
Near All India Radio,
Ahmedabad-9.

3. Shri B. S. Vaghela,
Sarpanch, Gram Panchayat,
Darbargadh, P.O. Gangad,
Taluka Dholka,
District Ahmedabad.
4. Shri Ratilal M. Andharla,
Campus Director,
The Gujarat Agricultural University,
Junagadh Campus, Junagadh.

3. Dr. B. N. Sahu,
Orissa University, of Agriculture and Technology,
Unit 8, Agricultural Colony,
Quarter No. 4, Type VI,
Bhubaneswar, ORISSA.

4. Shri Artison G. Monlu,
Professor of Economics,
Government College,
Upper Chandmari, Tura,
Garo Hills, Meghalaya.

BHOPAL LOCAL BOARD

1. Dr. Daya Shanker Nag,
Professor & Head of Department of
Post-Graduate Studies & Research
in Economics,
University of Jabalpur,
299, Napier Town,
Jabalpur.
2. Shri Ramakant Vishwanath Khode,
Director,
M.P. State Cooperative Bank,
Digthan Road,
Khargone (West Nimart),
Madhya Pradesh.
3. Shri Rewnath Chouhe,
Member,
Small Farmers' Development Agency,
Village Ridhora,
Post Pipla, Narainwar,
Distt. Chhindwara, Madhya Pradesh.
4. Shri Ganesh Prasad Varma,
Proprietor,
Khajuraho Arts,
Khajuraho, Distt. Chhatarpur,
Madhya Pradesh.
5. Shri Prem Swarup Kalani,
Director,
Indore Land & Finance Pvt. Ltd.,
Kamal Villa,
11, Tukoganj Road,
Indore.

HYDERABAD LOCAL BOARD

1. Dr. S. Bhagwantham,
Chairman,
Sri Sathya Electronics (P) Ltd.,
425, Rajmahal Extension,
Bangalore-6.
2. Shri E. B. V. Raghavaiah,
Managing Director,
Vijay Spinning Mills Ltd.,
Vijayawada.
3. Shri A. V. Pratap Reddy,
96, Adarshnagar,
Hyderabad-4.
4. Shri K. R. Choudary,
Managing Director,
Electric Transformer & Equipment Co.,
"Preeti",
215/2, Amirpet,
Hyderabad-16.
5. Shri A. Hanumantha Rao,
Hony. Bench Magistrate,
1st Class Bench Magistrate's Court,
Yadava Street,
Old Guntur, Guntur.

BOMBAY LOCAL BOARD

1. Shri A. R. Bhat,
Member,
National Productivity Council,
1218, Sadashiv Peth,
Poona-30.
2. Shri Neelkanth A. Kalyani,
Managing Director,
Bharat Forge Co. Ltd.,
49, Shri Shivaji Cooperative Housing Society,
Poona-16.
3. Shri B. R. Barwale,
Managing Director,
Maharashtra Hybrid Seed Corporation,
Jalna, Distt. Aurangabad.
4. Shri Anil Kumar Tumane,
Shukrawari, Nagpur.

KANPUR LOCAL BOARD

1. Dr. Baljit Singh,
Professor of Economics and Dean of the Faculty of Arts,
Lucknow University,
74, Badshah Bagh,
Lucknow.
2. Shri N. J. Khanna,
Director,
Cossul & Co. (P) Ltd.,
8/215, Aryanagar,
Kanpur.
3. Dr. S. K. R. Bhandari,
Senior Professor,
Faculty of Commerce & Business Management,
Banaras Hindu University,
C-2-1, Jodhpur Colony,
Varanasi.

CALCUTTA LOCAL BOARD

1. Shri Sukumar Roy,
Director,
The Shillong Hydro-Electric Company Ltd.,
51, Lansdowne Road,
Calcutta-25.
2. Shri D. N. Lahiri,
Partner,
Pioneer Engineering Corporation,
329, Jodhpur Park,
Calcutta-31.

4. Shri Ramprasad Tamta,
President,
Municipal Board,
"Hari Niwas",
Almora.
5. Prof. M. S. Khan,
Head of the Department of Economics
and Dean of the Faculty of Social Sciences,
Aligarh Muslim University,
Aligarh.

MADRAS LOCAL BOARD

Morabadi,
Ranchi-83008.[No. F. 9-2(15)/72-BO. I(III)]
D. N. GHOSH, Jt. Secy.

1. Shri K. M. Mamen Mappillai,
Managing Director,
Madras Rubber Factory,
71, G. N. Chetty Road,
Madras-17.
2. Shri K. S. Karayalar.
Director,
Travancore Rayons Ltd.,
Thycaud, Trivandrum.
3. Shri E. Gopalakrishna Rao,
Engineer Consultant,
"Anand Aram",
P.O. Kotekar, S. K. Vio Mangalore,
PIN.—574152.
4. Shri S. R. Kaiwar,
Director,
Seshasayee Paper & Boards Ltd.,
'Meru'
12 Crescent Second Road,
Gandhinagar, Madras-600020.
5. Shri K. S. Subramania Gounder.
President,
Tiruchengodu Coop. Marketing Society Ltd.,
Lakshmi Sadanam Konganpuram (Post).
Sankari Taluk,
Distt. Salem.

NEW DELHI LOCAL BOARD

1. Capt. Jai Singh Rathore,
Chairman,
Ajmer Central Coop. Bank,
Village & P.O. Para,
District Ajmer.
2. Smt. Vidya Stokes.
Partner,
M/s. Stokes Industries.
'Premel', P.O. Thanedhar,
Simla Hills.
3. Dr. B. M. Bhatia,
Principal,
Hindu College,
3, Imperial Avenue,
University Enclave,
Delhi University.
Delhi.
4. Shri Q. H. Farooque,
Senior Professor & Dean,
Faculty of Commerce,
Aligarh Muslim University.
Qamar Manzil,
Diggi Road, Aligarh.

PATNA LOCAL BOARD

1. Shri Ranchor Prasad,
Chairman,
Heavy Engineering Corporation,
3, Pataliputra Colony,
Patna.
2. Shri Nagin B. Parikh,
Managing Director,
Utkal Automobiles Pvt. Ltd.,
Main Road, Bistupur,
Jamshedpur.
3. Shri K. S. V. Raman,
400, Canal Boring Road,
Patna-1.
4. Shri Nagendra Narayan Sinha,
President,
Indian Council of Social Welfare,
Annie Besant Road,
Patna-4.
5. Swami Yuktananda,
Vice President,
Rama Krishna Mission Ashram,

नई दिल्ली, 3 मई, 1973

का. आ. 1482.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का दसवां) की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि अधिनियम की धारा 20 (1)(ख) (2) के उपबंध सिण्डिकेट बैंक पर, जहां तक उक्त उपबंध, मैसर्स

ए. के. लक्ष्मण गीवाड़ा एण्ड ब्रदर्स को, जिसके श्री ए. के. सुब्बया जो उक्त बैंक के निदेशक हैं, एक भागीदार हैं, ऋण या अग्रिम देने से निषिद्ध करते हैं, लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15(11)-बी. ओ. 3/73]

New Delhi, the 3rd May, 1973

S.O. 1482.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 20(1)(b)(ii) of the Act shall not apply to Syndicate Bank in so far as the said provisions prohibit any loan or advance being made to M/s. U. K. Laxman Gowda and Bros., of which Shri U. K. Subbiah, who is a director of the said bank, is a partner.

[No. 15(11)-B.O.III/73]

नई दिल्ली, 16 मई, 1973

का. आ. 1483.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का दसवां) की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के उपबंध बैंक आफ अमीरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सविंग्स एसोसिएशन, बम्बई पर इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबंध इसके प्रादेशिक उपाध्यक्ष और भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जॉन एम. अहरेन्स को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड का निदेशक होने का निबंध करते हैं जो समवाय अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं।

[संख्या एक. 15 (16) बी. ओ. 3/73]

डी. एम. सुकथनकर, निदेशक

New Delhi, the 16th May, 1973

S.O. 1483.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of the section 10 of the said Act shall not apply to Bank of America National Trust and Savings Association, Bombay, for a period of two years from the date of this notification, in so far as the said provisions prohibit Mr. John M. Ahrens, its Regional Vice President and Chief Executive Officer in India, from being a director of the Industrial Credit and investment Corporation of India Ltd., being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(16)-B.O.III/73]

D. M. SUKTHANKAR, Director.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

का० प्रा० 1484- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मई, 1973 की 4 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

वस्तु विभाज्य

नई दिल्ली, 11 मई, 1973

वैयताएं	रुपये	रुपये	प्रास्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	13,78,06,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट	55,98,95,33,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
जारी किए गए कुल नोट		5612,73,39,000	विदेशी प्रतिभूतियां	171,65,38,000	
			शेष		354,18,49,000
			रुपये का सिक्का		9,19,24,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5249,35,66,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे		..
			वाणिज्य पत्र		..
कुल वैयताएं		5612,73,39,000	कुल प्रास्तियां		5612,73,39,000

4 मई, 1973 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

वैयताएं	रुपये	प्रास्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	13,78,06,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	4,44,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	3,63,000
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	209,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	45,00,00,000	(क) देशी	18,46,17,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	175,00,00,000	(ख) विदेशी	..
जमा राशियां :—		(ग) सरकारी खजाना बिल	308,68,07,000
(क) सरकारी		विदेशी में रखा हुआ बकाया*	213,94,51,000
(i) केन्द्रीय सरकार	52,01,07,000	निवेश**	414,26,61,000
(ii) राज्य सरकारें	28,81,65,000	ऋण और अधिम :—	
(ख) बैंक		(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	302,57,59,000	(ii) राज्य सरकारों को †	70,25,00,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	13,94,29,000	ऋण और अधिम :—	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,96,08,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ‡	25,43,70,000
(iv) अन्य बैंक	38,72,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को @	225,41,69,000
		(iii) दूसरों को	4,16,57,000
(ग) अन्य	78,73,90,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण,	
देय बिल	82,57,11,000	अधिम और निवेश	
		(क) ऋण और अधिम	
अन्य वैयताएं	456,12,49,000	(i) राज्य सरकारों को	65,51,65,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,83,27,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	29,70,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,24,73,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अधिम	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अधिम	26,86,50,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से	
		ऋण, अधिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अधिम	95,09,36,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों	..
		में निवेश	..
		अन्य प्रास्तियां	57,38,94,000
रुपये	1601,12,90,000	रुपये	1601,12,90,000

*मकड़ी, प्राथमिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रवर्त ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं।

‡रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अधिम दिये गये 2,42,50,000 रुपये शामिल हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवर्त ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं।

एस० जगन्नाथन गवर्नर

तारीख 9 मई, 1973

[स० फ० 1 (1)/73-बी० प्रो० I]

ख० ब० मीरमन्तानी, प्रवर सचिव,

RESERVE BANK OF INDIA

S. O. 1484 An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 4th day of May, 1973.

ISSUE DEPARTMENT
New Delhi, the 11th May, 1973

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	13,78,06,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	5598,95,33,000		(a) Held in India	182,53,11,000	
Total Notes issued		5612,73,39,000	(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	171,65,38,000	
			TOTAL		354,18,49,000
			Rupee Coin		9,19,24,000
			Government of India		
			Rupee Securities		5249,35,66 000*
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		5612,73,39,000	Total Assets		5612,73,39,000

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India Banking Department as on the 4th May 1973

New Delhi, the 11th May, 1973

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	13,78,06,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	4,44,000
		Small Coin	3,63,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	209,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
		(a) Internal	18,46,17,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	45,00,00,000	(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	308,68,07,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	175,00,00,000	Balances Held Abroad*	213,94,51,000
		Investments**	414,26,61,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Central Government	..
(i) Central Government	52,01,07,000	(ii) State Government†	70,25,00,000
(ii) State Governments	28,81,65,000	Loans and Advances to :—	
(b) Banks		(i) Scheduled Commercial Banks‡	25,43,70,000
(i) Scheduled Commercial Banks	302,57,59, 000	(ii) State Co-operative Banks@	225,41,69,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	13,94,29,000	(iii) Others	4,16,57,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,96,08,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(iv) Other Banks	38,72,000	(a) Loans and Advances to :—	
(c) Others	78,73,90,000	(i) State Governments	65,51,65,000
Bills Payable	82,57,11,000	(ii) State Co-operative Banks	20,83,27,000
Other Liabilities	456,12,49,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	29,70,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,24,73,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	26,86,50,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	95,09,36,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	57,38,94,000
Rupees	1601,12,90,000	Rupees	1601,12,90,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund.

‡ Includes Rs. 2,42,50,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

S. JAGANNATHAN, Governor
[NO. F. 1(1)/73—BO. I]

Dated the 9th day of May, 1973.

C. W. MIRCHANDANI, Under Secretary.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 16th May, 1973

S.O. 1485.—In exercise of the powers conferred by the behalf, the President, after consultation with the Comptroller Constitution, and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Fifth Amendment Rules, 1973.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in the Fifth Schedule, in paragraph 2, after the entry "Additional Accountant General, Gujarat, Rajkot", the following entry shall be inserted, namely :—

"Director, National Civil Defence College, Nagpur".

[No. 13(1)-E.V.(B)/73]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय)

कानपुर, 26 मार्च, 1973

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

का. आ. 1486.—नियम 173 जी के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची की दौरेक मद सं. 14 बी बी के अन्तर्गत आने वाले 'सोडियम सिलिकेट' के निर्माण के लिए 'विलयशील कांच' को एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री के रूप में निर्धारित करता हूँ। सोडियम सिलिकेट का प्रत्येक विनिर्माता भी, जो विलयशील, कांच को मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में प्रयोग करता है, स्वनिर्धारण पर निकासी के कार्य विधि पुस्तिका (जुलाई 69 तक संशोधित) के पृष्ठ 23 के परिशिष्ट 2 के प्रपत्र (प्रपत्र 4) में विलयशील में विलयशील कांच का लेखा रखेगा।

[सं. 5/73]

ज्योतिर्मयवृत्त, समाहर्ता

(Central Excise Collectorate)

Kanpur, the 26th March, 1973

CENTRAL EXCISE

S.O. 1486.—In exercise of the powers conferred on me by sub-rule (4) of Rule 173-G, I hereby prescribe "Soluble Glass" as an additional important raw material for the manufacture of "Sodium Silicate" falling under tariff item No. 14BB of the first schedule to Central Excise and Salt Act, 1944. Every manufacturer of sodium silicate, who uses soluble glass as the intermediate product shall also maintain an account of soluble glass in form Annexure II (Form IV) appearing at page 23 of the SRP Hand Book. (corrected upto July, 1969).

[No. 5/73]

J. DATTA, Collector.

आवृश

बाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मई, 1973

का. आ. 1487.—यतः भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए कालीनों के निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कीतपत्र प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4049, तारीख 27 अक्टूबर, 1971 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (2), तारीख 27 अक्टूबर, 1971 में पृष्ठ 3013-3016 पर प्रकाशित किए गए थे ;

और यतः उसके द्वारा संभावितः प्रभावित होने वाले लोगों से 25 नवम्बर, 1971 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 27 अक्टूबर, 1971 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और यतः उक्त प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, एतद्वारा :—

(1) अधिसूचित करती है कि कालीन निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे ;

(2) कालीन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में, विनिर्दिष्ट करती है, जो ऐसे कालीनों पर निर्यात के पूर्व लागू होगा ;

(3) इस आवृश के उपाबंध में दिए गए विनिर्देशों के कालीनों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ;

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान कालीनों के निर्यात का सब तक प्रतिशोध करती है जब तक उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि इस प्रकार के कालीन निर्यात-योग्य हैं।

2. इस आवृश में "कालीन" से रोएंदार ऊनी सूत से बनाए गए प्रतिवर्ग मीटर/1,50,000 तक हाथ से लगाई गई गांठों का, धुलाई-योग्य, भारतीय ऊनी कालीन अभिप्रेत हैं तथा इसमें परिश्रम, मृशारिक, इंडो-बर्बर तथा अन्य डिजाइन भी सम्मिलित हैं।

3. इस आवृश की कोई बात भावी कंताओं को ऐसे कालीनों के नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनकी लम्बाई और चौड़ाई 60 सें. मी. से अधिक न हो।

4. यह आवृश 1 जुलाई 1973 को प्रवृत्त होगा।

उपाबंध

बनावट.—कालीनों का विनिर्माण—

(क) रंगों में से उनकी छीजन, कालीन की कतरनों, धूल, फालतू धागे आदि निकालकर साफ किए गए हथ के कतों/मिल के कतों ऊनी धागे से;

(ख) कम से कम 1.5 सें. मी. लंबी सादी या चित्रात्मक बुनाई की किनारी बनाकर, और झालर सहित बने कालीनों की दशा में, उसके बाध कम से कम 5 सें. मी. लम्बी प्रशित या जालीदार किनारी बनाकर, किया जाएगा।

2. लम्बाई और चौड़ाई—(1) कालीन की लंबाई और चौड़ाई संविदात्मक विनिर्देशों के अनुसार होगी। कालीन की लम्बाई और चौड़ाई दोनों पर +2.5 प्रतिशत का सहन अनुज्ञात होगा, जो कि लंबाई में 15 सें. मी. तथा चौड़ाई में 7.6 सें. मी. अधिक से अधिक होगा।

- (2) वी विकर्णा के मापों के औसत के आधार पर जब गणना की जाए कालीन के वीनों विकर्णा के मापों के बीच 2 से अधिक अन्तर नहीं होगा।

3. प्रतिवर्ग मीटर गांठ—गांठों की संख्या प्रतिवर्ग मीटर 12,000 से कम नहीं होगी और सीवदात्मक विनिर्देशों से + 5 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन नहीं होगा।

4. तैयारी की गहराई—तैयारी वाले भाग की गहराई सीवदा के अनुसार होगी और 10 मि. मी. (3/87) से कम नहीं होगी।

5. तैयारी की संरचना—तैयार धागा 100 प्रतिशत ऊनी होगा।

6. रंग का पक्कापन—रंगे हुए सूत का रंग, जल, कार्बोनिक विलायक के संसर्ग में आने पर तथा रगड़े जाने पर इतना पक्का होगा जितना नीचे दिया गया है, अर्थातः—

(1) जल के संसर्ग में—यदि उसे जल में डुबा दिया जाए और $37^{\circ}\text{C} \pm 2$ से. के तापमान पर 4.5 कि. ग्रा. के दाब के नीचे चार घंटे तक रखा जाए तो रंग छूटेंगे नहीं।

(2) कार्बोनिक विलायकों के संसर्ग में—यदि नमूना, विलायक में कक्ष-ताप पर 30 मिनट तक हिलाया जाता है और निचोड़ने के बाद $80^{\circ}\text{C} \pm 2$ से. पर छाया में सुखाया जाता है, तो धुलाई या मिल प्रसंस्करण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कार्बोनिक विलायकों के संसर्ग में आने पर रंगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी।

(3) रगड़े जाने पर—यदि कपड़े पर 900 ग्राम का दाब बिना कलफ के पर सफेद कपड़े के साथ इसे दस सेकंड तक रगड़ा जाता है, तो रंग नहीं निकलेगा। आसूत जल में भीगे हुए सफेद कपड़े के साथ 900 ग्राम के दाब के नीचे इस सेकंड तक भीगी दशा में रगड़े जाने पर, रंगों का कोई धब्बा सफेद कपड़े पर नहीं आएगा।

फिनिश—(1) तैयार कालीन उपरोक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-स सप्रद रूप में और एकसा बुना जाएगा और उसमें कोई कच्चे स्थल या अन्य विनिर्माण संबंधी दोष नहीं होंगे। सारी सतह वाले कालीनों के बारे में वे एक समान शब्द के होंगे।

(2) कालीन जब सपाट सतह पर फैलाया जाए तो उसमें कोई सिकड़ने और झुरियाँ दिखाई नहीं देंगी।

(3) परीक्षण डिजाइन के अर्थात् मुबारिक क्वालिटी के कालीन के मामले में यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि सब नगों के पृष्ठ-भाग धुलाई के पहले जला दिए गए हों। कालीनों की गठार भी पक्के रंग के रसायन में धुले ऊनी धागों से होंगी।

(4) चमकदार फिनिश देने के लिए कालीन रसायनों से धुले जाएंगे।

8. ज्वलनशीलता परख—संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात किए जाने वाले कालीन, यू. एस. डिपार्टमेंट आफ कामर्स द्वारा प्रकाशित डी. आ. सी. एफ. एफ. 2-70 में दी गई पद्धतियों के अनुसार सतही ज्वलन, शीलता परख के भी अधीन होंगे।

(9) लेबल लगाना—(1) 10.0×7.5 से. मी. आकार का लेबल कालीन के पीछे एक कोने पर मजबूती के साथ संलग्न किया जाएगा जिस पर निम्नलिखित जानकारी लिखी रहेगी, अर्थातः—

(1) आकार

(2) क्वालिटी (प्रति वर्ग मीटर गांठ)

(3) रंग जो, धुलाई और ड्राइक्लीनिंग पर पक्के बने रहेंगे।

(4) संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात किए जाने वाले कालीनों के मामले में यदि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की डिपार्टमेंट आफ कामर्स के मानक एफ. एफ. 2-70 की ज्वलनशीलता संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो लेबल पर निम्नलिखित कथन भी अंकित होगा :—

“ज्वलनशील (यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट आफ कामर्स के मानक एफ. एफ. 2-70 के अनुरूप नहीं हैं), इसका प्रयोग ज्वलनशीलों के निकट न किया जाए।

10. पैकिंग—कालीनों की पैकिंग सीवदा में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार की जाएगी।

[सं. 6(8)/71 नि. नि. सभा नि. सं.]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 26th May, 1973

ORDER

S.O. 1487.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting carpets to quality control and inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, at pages 3013-3016 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th October, 1971, under the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade, No. S.O. 4049, dated the 27th October, 1971;

And whereas objections and suggestions were invited till the 25th November, 1971, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 27th October, 1971;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that carpets shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Carpets (Quality Control and Inspection) Rules, 1973, as the type of inspection which shall be applied to such carpets prior to export;

(3) recognises the specifications as set out in the Annexure to this order, as the standard specifications for Carpets;

(4) prohibits the export, in the course of international trade, of carpets unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the Inspection Agencies recognised for the purpose under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such carpets are exportworthy.

2. In this order “carpet” means Indian hand knotted, washable, wollen carpet manufactured with wool pile yarn having upto 1,50,000 knots/sq. mtr. and shall include Persian, Mobarik, Indo-berber and other designs.

3. Nothing in this order shall apply to the export of samples of carpets to prospective buyers, the length and breadth of which does not exceed 60 centimetres.

4. This order shall come into force on 1st July, 1973.

ANNEXURE

1. **Construction.**—Carpets shall be manufactured with :

- (a) hand-spun/mill-spun woollen yarn free from wool waste, carpet clipping dust, burrs, etc., in the pile.
- (b) a band in plain or tapestry weave at least 1.5 cm. long followed by a knotted or netted fringe, at least 5 cm. long in case the carpets are manufactured with fringes.

2. **Length and width.**—(1) The length and width of the carpet shall be in accordance with the contractual specifications. A tolerance of ± 2.5 per cent both on the length and width of the carpet shall be permitted subject to a maximum of 15 cm. in length and 7.5 cm. in width.

(2) The measurements of two diagonals of a carpet shall not differ by more than 2 per cent when calculated on the basis of the average of the measurements of two diagonals.

3. **Knots per square meter.**—The number of knots shall not be less than 12,000 per sq. meter and shall not vary from the contractual specifications by more than ± 5 per cent.

4. **Depth of pile.**—The depth of pile shall be as contracted for and shall not be less than 10 mm. (3/8").

5. **Composition of piles.**—The pile yarn shall be 100 per cent wool.

6. **Colour fastness.**—The colour fastness of the dyed yarn to water, organic solvent and rubbing shall be as given below, namely :—

- (1) **Water fastness.**—The colour shall not bleed if soaked in water and kept under pressure of 4.5 Kg. at a temperature of $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ for four hours.
- (2) **Organic solvents fastness.**—The colours shall not react with the commonly used organic solvents used in cleaning or mill processing if a sample is agitated in solvent for 30 minutes at room temperature and after squeezing dried in shade at $80^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.
- (3) **Fastness to rubbing.**—The colour shall not come out if rubbed with unstained white cloth for ten seconds with a pressure of 900 grams on the cloth. In case of wet rubbing with white cloth soaked in distilled water for ten seconds at 900 grams pressure the colours shall not leave any mark on the white cloth.

7. **Finish.**—(1) The finished carpet shall in addition to satisfying the requirements given above, shall be firmly and uniformly woven and shall have no weak spots or other constructional defects. In the case of carpets with plain ground, these shall be of uniform shade.

(2) The carpets shall not show any creases and wrinkles when laid on a flat surface.

(3) In the case of Persian design carpet viz. Mobarik quality, it shall be ensured that the backs of all the pieces are burnt before washing. The binding of the carpets shall also be of fast colour chemically washed woollen yarn.

(4) The carpets shall be washed with chemicals to give a lustrous finish.

8. **Flammability test.**—Carpets meant for export to the United States of America, shall also be subjected to the surface flammability tests as per the methods given in DOC FF 2-70 published by the United States Department of Commerce.

9. **Labelling.**—(1) A label of size 10.0x7.5 cm. marked with the following information shall firmly be attached to one of the corners on the back of the carpet, namely :—

- (1) Size.....
- (2) Quality (knots per square meter).....
- (3) Colours fast to washing and dry cleaning.

(2) In case of carpets meant for exports to the United States of America not conforming to the flammability requirements of the United States Department of Commerce, Standard FF 2-70, the label shall also carry the following statement, namely :—

"FLAMMABLE (FALLS United States DEPARTMENT OF COMMERCE FF 2-70), SHOULD NOT BE USED NEAR SOURCES OR IGNITION".

10. **Packing.**—The carpets shall be packed in accordance with the requirements stipulated in the contract.

[No. 6(8)/71-EI&EP.]

का. आ. 1488.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. **सीक्षित नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम कालीन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973 हों।

(2) ये 1 जुलाई 1973 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत हों।

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत हों।

(ग) 'कालीन' से रोएदार ऊनी सूत से बनाए गए प्रतिवर्ग मीटर/1,50,000 तक हाथ से लगाई गई गाँठों का धुलाई-योग्य भारतीय ऊनी कालीन अभिप्रेत हों तथा इसमें पेशियन, मुबारिक, इन्डो-बर्बर तथा अन्य डिजाइन भी सम्मिलित हों।

3. **निरीक्षण का आधार.**—कालीनों का निरीक्षण यह देखने के लिए किया जायेगा कि, वे अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हों।

4. **निरीक्षण की प्रक्रिया.**—(1) कालीनों का निर्यात करने का आशय रखने वाला निर्यातकर्ता, ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना अभिकरणों में से किसी एक को वृत्ता ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना प्राप्त-भरण को संभावित तारीख से कम से कम सात दिन के पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुँच आएगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण कालीनों के परेक्षण का निरीक्षण यह देखने के लिए करेगा कि वह अधिनियम की धारा 8 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हों।

(4) यदि निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो गया है कि निर्यात किया जाने वाला कालीनों का परेक्षण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह उप-नियम (2) के अधीन सूचनाप्राप्ति के सात दिनों के भीतर परेक्षण को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए निर्यातकर्ता को प्रमाणपत्र दे देगा।

परन्तु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हुआ है वहाँ वह उक्त सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र

वैन से इन्कार कर देगा तथा इसके लिए कारण सहित ऐसे इन्कार की सूचना निर्यात-कर्ता को दे देगा।

5. निरीक्षण का स्थान.—इस नियम के प्रयोजनार्थ कालीनों का निरीक्षण या तो (क) विनिर्माता के परिसर पर या (ख) निर्यात-कर्ता के परिसर पर यदि वहाँ पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों किया जाएगा।

6. निरीक्षण फीस.—इन नियमों के अधीन परेषण के पांत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति एक सौ रूपये के लिए 50 पैसे की दर से फीस निरीक्षण-फीस के रूप में आवेदन के साथ दी जाएगी।

7. अपील.—नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र वैन के इन्कार से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इन्कार की सूचना उसको प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) उक्त पैनल की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति तीन विशेषज्ञों की होगी।

(3) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अंतिम होगा।

[सं. 6(8)/71-नि.नि. तथा नि.सं.]

S.O. 1488.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Carpets (Quality Control and Inspection) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on 1st July, 1973.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the Inspection Agencies recognised under section 7 of the Act;

(c) "Carpet" means Indian hand knotted, washable, woollen carpet manufactured with wool pile yarn having upto 1,50,000 knots/sq. mtr. and shall include Persian, Mobarik, Indo-berber and other designs.

3. **Basis of Inspection.**—Inspection of carpets shall be carried out with a view to see that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. **Procedure of inspection.**—(1) An exporter intending to export carpets shall give intimation in writing of his intention so to do to any one of the Agencies to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(2) Every intimation under sub-rule (1) shall reach the office of the Agency not less than seven days before the expected date of shipment.

(3) On receipt of the intimation under sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment of carpets with a view to see that the same conform to the specifications recognised under section 6 of the Act.

(4) If after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of carpets to be exported complies with the requirement of rule 3, it shall within seven days of the receipt of intimation under sub-rule (2), issue a certificate to the exporter declaring the consignment exportworthy:

Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reason therefor.

5. **Place of inspection.**—Inspection of carpets for the purpose of this rule shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer or (b) at the premises of the exporter, provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. **Inspection fee.**—A fee of 50 paise for every one hundred rupees of F.O.B. value of the consignment shall be paid as inspection fee under these rules alongwith the application.

7. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4 may, within 10 days of receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than 3 persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The quorum to constitute a meeting of the said panel shall be of its three experts.

(3) The decision of the said panel on such appeal shall be final.

[No. 6(8)/71-EI&EP]

का. आ. 1489.—निर्यात (कालिनी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कालीनों के निर्यात के पूर्व निरीक्षण के लिए निम्नलिखित निरीक्षण अभिकरणों को मान्यता प्रदान करती है, अर्थात्:—

1. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली, 13/37, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली-5.
2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई, 'अमन चेंबर' (चौथी मंजिल), 113, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-4.
3. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कलकत्ता, 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर', 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (7वीं मंजिल), कलकत्ता-1.
4. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मद्रास, 123, माउण्ट रोड, मद्रास-6.
5. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन, मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-11.

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना में कालीन से रोएंवार ऊनी सूत से बनाए गए प्रतिवर्ग मीटर 1,50,000 तक हाथ से लगाई गई गांठों का धुलाई-योग्य भारतीय ऊनी कालीन अभिप्रेत हैं तथा इसमें पर्सियन, मुबारिक, इंडो-बर्बर तथा अन्य डिजाइन भी सम्मिलित हैं।

[सं. 6(8)/71-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 1489.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the following Inspection Agencies for quality control and inspection of carpets prior to their export, namely:—

1. Export Inspection Agency—Delhi, 13/37, W.E.A. Arya Samaj Road, NEW DELHI-5.
2. Export Inspection Agency—Bombay, 113, M. Karve Road, Aman Chamber (4th floor), BOMBAY-4.
3. Export Inspection Agency—Calcutta, 14/1-B, Ezra Street, CALCUTTA-1.
4. Export Inspection Agency—Madras 123, Mount Road, MADRAS-6.

5. Export Inspection Agency—Cochin, Mahatma Gandhi Road, Manohar Building, Ernakulam, COCHIN-11.

Explanation:—

In this notification Carpet means Indian Hand Knotted, Washable, Woollen Carpets manufactured with wool pile yarn having upto 1,50,000 knots/sq. mtr. and shall include Persian, Moharik, Indo berber and other designs.

[No. 6(8)/71-LI&EP]

आवृत्ति

का. आ. 1490.—यतः केंद्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए भारत सरकार की विदेश व्यापार मंत्रालय की नाशिकीटमारों तथा उनके निरूपणों से संबंधित अधिसूचना सं. का. आ. 3310, तारीख 7 अक्टूबर, 1970 में निम्नलिखित रीति से संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है;

और यतः केंद्रीय सरकार ने निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित उस निमित्त प्रस्ताव निर्यात निरीक्षण परिष्कृत को भेज दिए हैं,

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव को उससे संभावित प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है।

2. यह सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति, जो उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे तो, उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर निर्यात निरीक्षण परिष्कृत 'वर्ल्ड ट्रेड रीस्टर' 14/1 बी, एनरा स्ट्रीट (7वीं मंजिल) कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3310, तारीख 7 अक्टूबर, 1970 में :—

(1) उपाबंध 1 में, क्रम सं. 19 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

20. बिनापाकाइल पायसीय दाने
21. क्लोरहेन बुकनी
22. क्लोरहेन पायसीय दाने
23. क्यूप्रस आक्साइड बुकनी
24. क्यूप्रस आक्साइड जल विच्छेद्य चूर्ण दाने
25. हायाजिनन पायसीय दाने
26. हायाजिनन जल में विच्छेद्य चूर्ण-दाने
27. हा. लोखांस पायसीय दाने
28. हाइकोफोस पायसीय दाने
29. हाइलिट्रिन जल में विच्छेद्य चूर्ण दाने
30. हाइमेथॉट पायसीय दाने

31. पायसीय लाखानाशी तेल, पाइरेथ्रम आधारित
32. एंडोसल्फन बुकनी
33. एंडोसल्फन पायसीय दाने
34. फौनीट्रोथियन पायसीय दाने
35. जमायें हुए एथोक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड के दानों पर आधारित औषधियां
36. घरेलू कीटनाशक छिड़कने की दवा
37. चूना गन्धक घोल
38. मैलेथियन बुकनी
39. मैलेथियन जल में विच्छेद्य चूर्ण-दाने
40. मिथाइल-पैराथियन पायसीय दाने
41. ओरगोनो मस्कुरिया झड़ सीड डीसिंग औषधियां
42. पाइरेथ्रम पायसीय दाने
43. गंधक चूर्ण, आर्द्रणीय
44. थियोमेटोन पायसीय दाने
45. थिरम सीड डीसिंग औषधियां
46. बार्पेरिन चारों के लिए दाने
47. जाइनेब जल में विच्छेद्य चूर्ण
48. जाइरम जल में विच्छेद्य चूर्ण
49. एंडोसल्फन जल में विच्छेद्य चूर्ण
50. थाइरम जल में विच्छेद्य चूर्ण
51. गामा-बी एच.सी (लिण्डेन) धुआंकारक।"

(2) उपाबंध 2 में क्रम सं. 19 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- | | |
|---|-------------------|
| 20. बिनापाकाइल पायसीय दाने | भा. मा. 4325-1967 |
| 21. क्लोरहेन बुकनी | भा. मा. 2864-1964 |
| 22. क्लोरहेन पायसीय दाने | भा. मा. 2682-1966 |
| 23. क्यूप्रस आक्साइड बुकनी | भा. मा. 1669-1960 |
| 24. क्यूप्रस आक्साइड जल में विच्छेद्य चूर्ण-दाने | भा. मा. 1665-1960 |
| 25. हायाजिनन पायसीय दाने | भा. मा. 2861-1964 |
| 26. हायाजिनन जल में विच्छेद्य चूर्ण-दाने | भा. मा. 2862-1964 |
| 27. हाइकोफोस पायसीय दाने | भा. मा. 5277-1969 |
| 28. हाइकोफोस पायसीय दाने | भा. मा. 5279-1969 |
| 29. हाइलिट्रिन जल में विच्छेद्य चूर्ण-दाने | भा. मा. 1053-1962 |
| 30. हाइमेथॉट पायसीय दाने | भा. मा. 3903-1966 |
| 31. पायसीय लाखानाशी तेल, पाइरेथ्रम आधारित | भा. मा. 6014-1970 |
| 32. एंडोसल्फन बुकनी | भा. मा. 4322-1967 |
| 33. एंडोसल्फन पायसीय दाने | भा. मा. 4323-1967 |
| 34. फौनीट्रोथियन पायसीय दाने | भा. मा. 5281-1969 |
| 35. जमायें हुए एथोक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड के दाने पर आधारित औषधियां | भा. मा. 2359-1963 |

36. घरेलू कीटनाशक छिड़कने की दवा भा. मा. 1824-1961
37. सूना गन्धक घोल भा. मा. 1050-1957
38. मेलैथियम कृकनी भा. मा. 2569-1963
39. मेलैथियम जल में विच्छेद्य चूर्ण दाने भा. मा. 2569-1963
40. मिथाइल-पैराथियम पायसीय दाने भा. मा. 2865-1964
41. ऑसोनो मरकुरिया डाइ सीड ड्राईसिंग ऑषधियां भा. मा. 3264-1965
42. पाइरेथ्रम पायसीय दाने भा. मा. 4808-1968
43. गंधक चूर्ण, आद्रणीय भा. मा. 3383-1965
44. थियोमेटोन पायसीय दाने भा. मा. 3905-1966
45. थिरम सीड ड्राईसिंग सीड ऑषधियां भा. मा. 4783-1968
46. वारफारिन चारे के लिए दाने भा. मा. 5549-1970
47. जाइनेब जल में विच्छेद्य चूर्ण भा. मा. 899-1966
48. जाइरम जल में विच्छेद्य चूर्ण भा. मा. 3901-1966
49. एंडोसल्फन जल में विच्छेद्य चूर्ण दाने भा. मा. 1324-1967
50. थाइरम जल में विच्छेद्य चूर्ण भा. मा. 4766-1968
51. गामा-बी एच सी (लिनडने) धूआंकारक भा. मा. 1505-1968

[सं. 6(39)/72-नि. नि. तथा नि. वृद्धि]

म. क. ब. भटनागर, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1490.—Whereas the Central Government is of opinion that, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade, No. S.O. 3310, dated the 7th October, 1970 relating to pesticides and their formulations, in the manner specified below for the development of the export trade of India;

And whereas the Central Government has forwarded the proposals in that behalf to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same, within thirty days from the date of publication of this order in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

Proposals

In the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade, No. S.O. 3310, dated the 7th October, 1970,—

(i) in Annexure I, after Serial Number 19 and the entry relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

- "20. Binapacryl emulsifiable concentrates.
21. Chlordane dusting powders.
22. Chlordane emulsifiable concentrates.
23. Cuprous oxide dusting powders.
24. Cuprous oxide water dispersible powder concentrates.
25. Diazinon emulsifiable concentrates.
26. Diazinon water dispersible powder concentrates.
27. Dichlorvos emulsifiable concentrates.
28. Dicofol emulsifiable concentrates.
29. Dieldrin water dispersible powder concentrates.
30. Dimethoate emulsifiable concentrates.
31. Emulsifiable larvicidal oil, pyrethrum based.

32. Endosulfan dusting powders.
33. Endosulfan emulsifiable concentrates.
34. Fenitrothion emulsifiable concentrates.
35. Formulations based on stabilized ethoxy ethyl mercury chloride concentrate.
36. Household insecticidal spray.
37. Lime sulphur solution.
38. Malathion dusting powders.
39. Malathion water dispersible powder concentrates.
40. Methyl-parathion emulsifiable concentrates.
41. Organo-mercurial dry seed dressing formulations.
42. Pyrethrum emulsifiable concentrates.
43. Sulphur powder, wettable.
44. Thiometon emulsifiable concentrates.
45. Thiram seed dressing formulations.
46. Warfarin bait concentrates.
47. Zineb water dispersible powder.
48. Ziram water dispersible powder.
49. Endosulfan water dispersible powder concentrates.
50. Thiram water dispersible powder.
51. Gamma-BHC (lindane) smoke generators."

(ii) in Annexure II, after Serial Number 19 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

- "20. Binapacryl emulsifiable concentrates. IS : 4325—1967
21. Chlordane dusting powders. IS : 2864—1964
22. Chlordane emulsifiable concentrates. IS : 2682—1966
23. Cuprous oxide dusting powders. IS : 1669—1960
24. Cuprous oxide water dispersible powder concentrates. IS : 1665—1960
25. Diazinon emulsifiable concentrates. IS : 2861—1964
26. Diazinon water dispersible powder concentrates. IS : 2862—1964
27. Dichlorvos emulsifiable concentrates. IS : 5277—1969
28. Dicofol emulsifiable concentrates. IS : 5279—1969
29. Dieldrin water dispersible powder concentrates. IS : 1053—1962
30. Dimethoate emulsifiable concentrates. IS : 3903—1966
31. Emulsifiable larvicidal oil, pyrethrum based. IS : 6014—1970
32. Endosulfan Dusting powders. IS : 4322—1967
33. Endosulfan emulsifiable concentrates. IS : 4323—1967
34. Fenitrothion emulsifiable concentrates. IS : 5281—1969
35. Formulations based on stabilized ethoxy ethyl mercury chloride concentrate. IS : 2359—1963
36. Household insecticidal spray. IS : 1824—1961
37. Lime sulphur solution. IS : 1050—1957
38. Malathion dusting powders. IS : 2568—1963
39. Malathion water dispersible powder concentrates. IS : 2569—1963
40. Methyl-parathion emulsifiable concentrates. IS : 2865—1964
41. Organo-mercurial dry seed dressing formulations. IS : 3284—1965
42. Pyrethrum emulsifiable concentrates. IS : 4808—1968
43. Sulphur powder, wettable. IS : 3383—1965
44. Thiometon emulsifiable concentrates. IS : 3905—1966
45. Thiram seed dressing formulations. IS : 4783—1968
46. Warfarin bait concentrates. IS : 5549—1970
47. Zineb water dispersible powder. IS : 3899—1966
48. Ziram water dispersible powder. IS : 3901—1966
49. Endosulfan water dispersible powder concentrates. IS : 4324—1967
50. Thiram water dispersible powder. IS : 4766—1968
51. Gamma-BHC (Lindane) smoke generators. IS : 1505—1968"

[No. 6(39)/72-EI&EP]

M. K. B. BHATNAGAR, Under Secy.

(आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

का. आ. 1491.—केंद्रीय सरकार अधिनियम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दी गई मान्यता के नवीकरण के लिए दी सेंट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा आवेदन पर, घायदा बाजार आयोग से परामर्श करके विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलसी के अधिनियम संविदाओं की बाबत उक्त एक्सचेंज को 1 जून, 1974 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की और कालावधि के लिए एतद्वारा मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा दी गई मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[फा. सं. 12 (4) आई. टी./73]

यू. एस. राणा, संयुक्त निदेशक

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 10th May, 1973

S.O. 1491.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Central India Commercial Exchange Ltd., Gwalior, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year ending the 1st June 1974, in respect of forward contracts in linseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(4)-IT/73.]

U. S. RANA, Jt. Director.

(मुख्य निबंधक, आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 1973

का. आ. 1492.—मुख्य क्रय अधिकारी, बीज क्रय संगठन, तलवार टाउनशिप (पंजाब) को 800 रु. (आठ सौ रु. मात्र) के लिए एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. जी/जे/3037952/एन/46/एच/35-36 दिनांक 2-2-1973 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुमतिपत्र जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका उपयोग बिलकूल नहीं किया गया था।

2. इस तर्क की पुष्टि में आवेदक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के शपथ अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यीकृत एक शपथ पत्र दाखिला किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया है। इस लिए यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7.12.1955 की उपधारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रय अधिकारी, बीज क्रय संगठन, तलवार टाउनशिप (पंजाब) को जारी

किया गया मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. जी/जे/3037952/एन/46/एच/35-36 दिनांक 2.2.1973 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुमतिपत्र प्रती लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या : सी जी 2/आई एंड पी (178)/72-73]

एन. सी. कान्जीलाल, उप मुख्य नियंत्रक

Office of the Chief Controller of Imports & Exports :

ORDER

New Delhi, the 4th May, 1973.

S.O. 1492.—The Chief Purchase Officer, Beas Purchase Organisation, Talwara Township (Punjab) were granted a C.C.P. No. G/J/3037952/N/46/H/35-36 dated 2nd February, 1973 for Rs. 800 (Rupees eight hundred only). They have applied for the issue of a duplicate copy of the said CCP on the ground that the original CCP has been lost/misplaced. It is further stated that the original C.C.P. was not registered with any Custom Authority or utilized at all.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly attested by the Oath Commissioner, High Court of Delhi. I am accordingly satisfied that the original CCP has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the imports (Control) order 1955 dated 7th December, 1955 as amended, the said original CCP No. G/J/3037952/N/46/H/35-36 dated 2nd February, 1973 issued to The Chief Purchase Officer, Beas Purchase Organisation, Talwara Township (Punjab) is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the said CCP is being issued separately to the licensee.

[No. CG. II/I&P(178)/72-73]

N. C. KANJILAL, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1973

का. आ. 1493.—सर्वश्री स्काउट कीमकल इंडस्ट्रीज, छोटी बाजार, चावल मंडी को कानूनी वेक्स, तथा मोटन वेक्स के आयात के लिए प्रत्येक 5000 रु. के लिए आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1717149 तथा पी/एस/171750 दोनों का दिनांक 29-7-72 है, स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने उपयुक्त दोनों लाइसेंसों की अनुमतिपत्र प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उपयुक्त दोनों लाइसेंसों की मूल प्रतियां बिना उपयोग किए ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक, 1972-73 की कंडिका 318 (2) के अंतर्गत अपेक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उपयुक्त दोनों लाइसेंसों की प्रतियों में खो गए/अस्थानस्थ हो गए हैं।

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं दोनों आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1717149 तथा पी/एस/171750 को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

4. आवेदक को अब उपयुक्त दो लाइसेंसों के बदले अनुमतिपत्र लाइसेंस के दो सेटों को जारी करने के मामले पर आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक, 1972-73 की कंडिका 318 (1) के अनुसार विचार किया जाएगा।

[संख्या एन पी/एस/32/ए एम-72/एयू. पी. बी. सी. एल. ए.]

कै. आर. धीर, उप मुख्य निबंधक

कुल सं. मू. नि.

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 13th February, 1973

S.O. 1493.—M/s. Scout Chemical Industries, Khoti Bazar, Chawal Mandi, Amritsar, were granted two import licence Nos. P/s/1717149 and P/s/1717150 both dated 29th July 1972 for each for Rs. 5000 for import of Carnuba Wax and Montan Wax. They have applied for issue of duplicate copies of the said two licences on the ground that both the copies of the said two licences have been lost/misplaced, without having been utilized.

2. The applicant have filed an affidavit on stamped paper, in support of their contention, as required under para 318(2) of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure for 1972-73. I am satisfied that the said both the licences in duplicate, have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under clause 9(cc) Import (Control) Order 1955 dt. 7th December, 1955 as amended upto date, I order the cancellation of the two import licences nos. P/s/1717149 and P/s/1717150.

4. The applicants case will now be considered for the issue of two sets of duplicate licences in lieu of the said two licences in accordance with para 318(1) of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73.

[No. NP/S/32/ART-72/AV. PB. CLA]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller

for Jt. Chief Controller

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

बङ्गौरा, 16 मई, 1973

का. आ. 1494.—यत्तः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकृतिगत भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में जी. जी. एस. 5 से जंक्शन प्वाइंट तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है।

और यतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 31-8-1970 को उस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट संप्रक्रिया के पर्यवेक्षण कर दिया है।

अब अतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम

प्रौद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारतीय मानक सस्था)

नई दिल्ली, 14 मई, 1973

का. प्रा. 1495. समय समय पर संशोधित भारतीय मानक सस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 11 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक सस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सीएम/एल-1726 जिसके ध्येय नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म द्वारा एल पी जी मिलेण्डरो का उत्पादन बढ़ कर देने के कारण 15 जनवरी, 1973 से रद्द कर दिया गया है:

अनुसूची

लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंस धारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया
सी एम/एल-1726 18-6-1968	मैसर्स प्रिजय स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, डाकघर राजवध (पूर्वी रेलवे) जिला बर्दवान (पं० बंगाल) (कार्यालय 'प्रिजय हाऊस' 15 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16 में है)	अल्पबाष्प द्रवणीय पेट्रोलियम गैसों के भंडारण और परिवहन के लिए 26.9 लीटर और 33 लीटर जल समाईवाले वेल्ड्ड अल्प कार्बन गैस सिलेण्डर (IS : 3196-1966)

[सी एम डी/55: 1726]

प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संप्रक्रिया के पर्यवेक्षण के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

अनुसूची

जी जी एम व से जंक्शन प्वाइंट तक पाइपलाइन की संप्रक्रिया का पर्यवेक्षण

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	संप्रक्रिया के पर्यवेक्षण की तारीख
-----------------	------	------------------	--------------------------------------	------------------------------------

पेट्रोलियम और रसायन	इसन्द	5287	4-12-1971	31-8-1970
---------------------	-------	------	-----------	-----------

[सं. 11(1)/72 एल. एण्ड एल.]

जे. पी. बालीवाल

गुजरात के लिये अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

Baroda, the 16th May, 1973

S.O. 1494.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from GGS V to Jn. Point in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil and Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 31-8-1970.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation referred to above.

Schedule

Termination of operation of pipeline from G. G. S. V. JUNCTION POINT

Name of Ministry	Village	S. O. in the Govt. No. Gazette of India.	Date of publication	Date of termination of operation.
PETROLEUM & CHEMICALS	Isand	5287	4.12.1971	31.8.1970

[No. 11/1/72-L&I.]

J. P. BALIWALA, Competent Authority

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY
(INDIAN STANDARDS INSTITUTION)**

New Delhi, the 14th May, 1973

S.O. 1495.—In pursuance of sub-regulation (4) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L—1726 particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 15 January 1973 as the firm has stopped production of LPG cylinders :

SCHEDULE

Licence No. and Date	Name and Address of the Licensee	Article/Process Covered by the licence Cancelled & the Relevant Indian Standard
CM/L—1726 18-6-1968	M/s Apecjay Structural Limited, P.O. Rajbandh (E. Rly.), Distt. Burdwan, West Bengal having their Office at "Apecjay House", 15 Park Street, Calcutta-16.	Welded low carbon Gas cylinders of 26-9- litres and 33 litres water capacity for the storage and transportation of liquifiable petroleum gases (IS : 3196—1968)

[CMD/5 : 1726]

नई दिल्ली, 15 मई, 1973

क्र० प्रा० 1496.—समय समय पर सशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन बिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अनुसार IS:3309-1965 में दिए गए उपबन्ध, जिनका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है। मानक चिन्ह के प्रयोग में गति खाने के उद्देश्य से परीक्षात्मक रूप में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय मानक के अनुसार बने माल की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिसूचना तुरन्त ही लागू हो जाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानक संख्या और शीर्षक जिसके उपबन्धों में संशोधन किया गया	उपबन्धों में किए गए संशोधन का विवरण
1	2	3
1.	IS:3309-1965 घुलनशील काफीचकोरी पाउडर की विशिष्टि	माल को टिन-प्लेट अथवा कांच के बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य बर्तनों में पैकिंग की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से खंड 3.1 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:— “3.1 पैकिंग—माल को 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम अथवा ऐसी किसी भी मात्रा में खरीददार और विक्रेता जिसे आपस में तय कर लेवे, वायु-रोधी टिन-प्लेट अथवा कांच के बर्तनों में पैक किया जा सकेगा। 200 ग्राम तक के पैकिंग के लिए वायु-रोधी टिन-प्लेट अथवा कांच के चमकदार बर्तनों का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसी अवस्था निम्नलिखित टिप्पणी सावधानी के लिए मुद्रित करनी होगी:— पैकिंग को एक बार खोलने के बाद माल को तुरन्त ही वायु-रोधी बर्तन में बदल देना चाहिए।”

[स० सी एम डी/13.4]

एस० के० सेन, महानिदेशक

New Delhi, the 15th May, 1973

S.O. 1496.—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, modifications to the provisions of IS : 3309-1965, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This notification shall come into force with immediate effect :

SCHEDULE

Sl. No. and Title of Indian Standard, the Provisions of which have been Modified	Particulars of the Modifications made to the Provisions
(1)	(2)
1. IS:3309-1965 Specification for soluble Coffee-chicory powder	With a view to permit packing of material in containers other than tin-plate or glass containers ; Clause 3.1 has been amended to read as follows : “3.1 Packing—The material shall be packed in 50g, 100g, 200g or any other quantity as agreed to between the purchaser and the vendor, in air-tight tin-plate or glass containers. For packs up to 200g, in addition to air-tight tin-plate or glass containers, suitable plastic or metal foil laminate containers may also be used in which case a cautionary note to the following effect shall be printed : Once this pack is opened, the contents should be immediately transferred to an air-tight container.”

[No. CMD/13:4]

S.K. Sen, Director General

स्वात और खान मंत्रालय
(खान विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1973

का०प्रा० 1497.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार, स्वात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 3412 तारीख 13 नवम्बर, 1972 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 195.00 एकड़ (लगभग) या 78.91 हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आणय की सूचना दे दी थी,

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित समस्त भूमि में कोयला उपलब्ध है ;

अतः अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाखण्ड अनुसूची में वर्णित 195.00 एकड़ (लगभग) या 78.91 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमि में खनिजों के खनन, खदान क्रिया, घोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने और ले जाने के अधिकारों को अर्जित करने के अपने आणय की एतद्द्वारा सूचना देती है।

टिप्पण-1 : इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण कलक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाऊस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण-2 : कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अन्तर्गत उपबन्धों की ओर एतद्द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध है :—

“8(1) किसी ऐसी भूमि में, जिसके बारे में धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस (30) दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या उस पर किसी अधिकारी के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:—किसी व्यक्ति का यह कहना कि वह स्वयं कोयले के उत्पादन के लिए भूमि के खनन सक्रियाएं आरम्भ करना चाहता है और यह कि ऐसी सक्रियाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आरम्भ नहीं की जानी चाहिए, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आक्षेप नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को स्वयं या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे सब आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अनिवार्य जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि या ऐसी भूमि में अथवा उन पर अधिकारों के संबंध में रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न भूमि खंडों या ऐसे भूमि खंडों में अथवा उन पर अधिकारों के बारे में विभिन्न रिपोर्टों, आक्षेपों पर अपनी निष्कारिणों और अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख सहित, केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लिए भेजेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो यदि इस अधिनियम के अधीन वह भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर कोई अधिकार अर्जित किए जाएं तो, प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा।

टिप्पण-3 : कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अनुसूची

कैम्पटी खंड - 'ख' विस्तारण का विस्तार

कैम्पटी कोयला क्षेत्र

डाइग मख्या राजस्व/92/72

तारीख 22-12-72

(उस भूमि को दर्शित करने वाली जिनमें खनिजों के खनन, खदान क्रिया, घोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए गए हैं)

खनन अधिकार

क्रम संख्या	ग्राम	तहसील	मोजा संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	कोडास	माधोनेर	52	नागपुर	भाग	

कुल 195.00 एकड़ (लगभग)
या 78.91 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम कोडास में अर्जित किए जाने वाले प्लोटों की संख्या :—

111(पी), 153(पी), 154(पी), 155(पी), 156(पी), 157(पी), 158, 159, 160(पी), 161, 162, 163, 164, 165(पी), 166 (पी), 167(पी), 168(पी), 169(पी), 170(पी), 171(पी), 172(पी), 173 (पी), 174 (पी), 175 (पी), (176 पी), 177, 178, 179, 180/1, 180/2, और 181 से 192

सीमा वर्णन :

क-ख लाइन ग्राम कोडास में प्लोट संख्या 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 111 और 176 से होकर गुजरती है।

ख-ग लाइन सड़क की भागत. उत्तरी सीमा के साथ ग्राम कोडास में होकर गुजरती है।

ग-घ लाइन कोडास और पिपला ग्रामों की भागत. सामान्य सीमा के साथ होकर गुजरती है।

घ-क लाइन ग्राम कोडास में प्लोट संख्या 153, 154, 155, 156, 157, 160, 166 और 167 से होकर गुजरती है और प्रारम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं० 25(6)/72-को० 5]

ए० एम० वेशपाडे, अवसर सचिव,

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, 14th May, 1973

S.O. 1497.—Whereas by the notification of the Government of India Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3412 dated the 13th October, 1972, issued under Sub-section(1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 195.00 acres (approximately) or 78.91 hectares (approximately) of lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in whole of the land notified under sub-section (1) of section 4 of the said Act ;

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 195.00 acres (approximately) or 78.91 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto ;

Note—1. The Plan of the areas covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Nagpur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note—2. Attention is hereby invited to the provision under section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 which provides as follows

“8 (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days (30 days) of the issue of the notification object to the acquisition of the whole any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation :—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector and opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceeding held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such were acquired under this Act.”

Note—3. The Coal Controller, 1, Council House, Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act.”

SCHEDULE

Extention to Kamptee Block— ‘B’ Extn.
Kamptee Coalfield

DRG No Rev/92/72
dated 22-12-72

(Showing lands where rights to mine, quarry, bore dig and search for, win, work and carry away minerals are to be acquired.)

Mining Right :—

Serial Number	Village	Tahsil	Mouza Number	District	Area	Re-marks
1.	Kodas	Saoner	52	Nagpur		Part
			Total :	195.00 acres (Approximately) 78.91 Hectares	"	

Plot numbers to be acquired in village Kodas :—

111 (P), 153 (P), 154 (P), 155 (P), 156 (P), 156 (P), 157 (P), 158, 159, 160 (P), 161, 162, 163, 164, 165, 166 (P), 167 (P), 168 (P), 169 (P), 170 (P), 171 (P), 172 (P), 173 (P), 174 (P), 175 (P), 176 (P), 177, 178, 179, 180/1, 180/2, & 181 to, 192.

Boundary Description :—

A-B Line passes through plot numbers 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 111 and 176 of village Kodas.

B-C Line passes along the part northern boundary of Road passes through village Kodas.

C-D Line passes along the common boundary of villages Kodas & Pipala.

D-A Line passes through plot numbers 153, 154, 155, 156, 157, 160, 166 and 167 of village Kodas and meets at starting point ‘A’.

A.S. DESHPANDE, Under Secy.

[No. 25 (6)/72—C5]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संस्थालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

का०आ० 1498.—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 (1970 का 48) की प्रथम अनुसूची के पैरा 1 का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्धारित करती है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में नियत सीटों में जम्मू, कश्मीर राज्य की एक सीट आयुर्वेद तथा एक यूनानी की होनी और भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (स्वास्थ्य विभाग) की 10 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या एफ 3/9/69-आयु० शि० में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में सारणी के कालम 1 के अधीन ‘हरियाणा’ प्रविष्टि और इससे संबंधित प्रविष्टि के कालम 2 के बाद कालम 1 और 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख ली जाय, नामतः

राज्य का नाम	उनके लिए सीटें		
	आयुर्वेद	सिद्ध	यूनानी
जम्मू और कश्मीर	1		1
1		2	

प्रकाश चन्द अरोड़ा
धरार सचिव,

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Health Department)

New Delhi, the 10th May, 1973

S.O. 1498.—In pursuance of paragraph I of the First Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby determines that the number of seats allocated in the Central Council of Indian Medicine to each of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems of Medicine shall, in respect of the State of Jammu and Kashmir, be one seat for Ayurveda and one seat for Unani and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. F. 3—9/69-AE, dated the 10th August, 1971, namely:

In the said notification, in the Table, under column 1, after the entry 'Haryana' and its connected entry in column 2, the following entries in columns 1 and 2 shall be made, namely :—

Name of State	Number of seats for		
	Ayurveda	Siddha	Unani
1	2		
Jammu and Kashmir	1	..	1

[No. F. 3—47/AE]

P. C. ARORA, Under Secy.

नौबहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 15 मई, 1973

का. आ. 1499.—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 42 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्त विनिर्दिष्ट करती हैं, अर्थात्:—

शर्त

1. यदि परिवहन गाड़ी एक नई गाड़ी है, तो मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 25 के अंतर्गत जारी किये गए अस्थायी रजिस्ट्रेशन का बंध प्रमाण-पत्र इस गाड़ी पर प्रदर्शित किया जाएगा।

2. यदि परिवहन गाड़ी एक नई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी के विक्रेता द्वारा दिया गया एक अक्षर इस गाड़ी पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसपर खरीदने वाले व्यक्ति का नाम और वह स्थान लिखा जायेगा जहाँ गाड़ी जा रही है।

[संख्या 39-टीएजी(12)/70-2]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 15th May, 1973

S.O. 1499.—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of section 42 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby specifies for the purposes of the said clause, the following conditions, namely:—

Conditions

1. If the transport vehicle is a new vehicle a valid certificate of temporary registration issued under section 25 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), shall be displayed on such vehicle.

2. If the transport vehicle is not a new vehicle a letter from the seller of the vehicle stating the name of the person to whom it has been sold and the place to which it is proceeding shall be displayed on such vehicle.

[No. 39-TAG(12)/70-1I]

का. आ. 1500.—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 42 की उप-धारा (3) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करती हैं, अर्थात्:—

प्रयोजन

1. अन्य परिवहन गाड़ी के स्थान पर भेजी जा रही परिवहन गाड़ी।

2. बड़े के स्वामी द्वारा किसी दूसरे व्यापार स्थान पर भेजी जा रही परिवहन गाड़ी जब कि वहाँ उसका व्यापार स्थानांतरित हो जाता है।

[संख्या 39-टीएजी(12)/70-3]

S.O. 1500.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (3) of section 42 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby specifies, for the purposes of the said clause, the following purposes, namely:—

Purposes

1. A transport vehicle being sent as a replacement for another transport vehicle.

2. A transport vehicle being sent to another place of business by a fleet owner on transfer of his business to such place.

[No. 39-TAG(12)/70-1II]

का. आ. 1501.—मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 56) की धारा (1) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा जून, 1973 की पहली तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (ख) के उपबंधों के लागू होने की तारीख के रूप में निश्चित करती हैं।

[संख्या 39-टीएजी(12)/70-4]

S.O. 1501.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section (1) of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1969 (56 of 1969), the Central Government hereby appoints the first day of June, 1973, as the date on which the provisions of clause (b) of section 17 of the said Act shall come into force.

[No. 39-TAG(12)/70-IV]

का. आ. 1502.—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 42 की उपधारा (3) के खण्ड (एफ एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित प्रयोजनों और शर्तों को एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती हैं, अर्थात्:—

सारणी

भाग 1—प्रयोजन

(क) प्रदर्शन।

(ख) विज्ञापन।

(ग) लम्बे और भिन्न भूमि पर सड़क परीक्षण तथा सहन शक्ति परीक्षण।

(घ) जांच भूमि।

(ङ) निर्यात

भाग 2—शर्तें

1. भाग 1 की मर्दानों (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिवहन गाड़ी पर एक अक्षर दिखाया जाएगा जो कि ऐसी गाड़ी के मार्ग और यथावस्था उन जगहों का जहाँ प्रदर्शन किया जाना है या विज्ञापन दिया जाना है और प्रत्येक ऐसे स्थान पर ठहरने की अवधि दिखायेगा।

2. भाग 1 की मर्दानों (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग की जा रही गाड़ी—

- (1) एक ऐसा अक्षर दिखाएगी जो कि उस प्रयोजन को सूचित करेगा जिसके लिए गाड़ी का प्रयोग हो रहा है और उस स्थान या स्थानों का निर्देश करेगा जहाँ वह जा रही है,
- (2) राज्य में प्रवृत्त मोटर गाड़ी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यापार प्रमाणपत्र दिखाएगी,
- (3) औजारों और उपकरणों के अतिरिक्त कोई सामान या चालक एक मैकेनिक और दो परिचरों के अतिरिक्त कोई दूसरा यात्री नहीं उठाएगी तथा प्रत्येक ऐसे चालकों मैकेनिकों और परिचरों के पास पहचान कार्ड या पत्र होंगे जो कि उस व्यक्ति द्वारा जारी किए गए हों जो कि मोटर गाड़ियों के निर्माता या व्यापारी हैं या वेसिस के साथ लगाने के लिए बाँटियों का निर्माण करते हैं।

[सं. 39-टीएजी(12)/70-1]

एन. ए. ए. नारायणन, अवर सचिव.

S.O. 1502.—In exercise of the powers conferred by clause (ff) of sub-section (3) of section 42 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby specifies, for the purposes of the said clause, the purposes and conditions mentioned in the Table below, namely:—

TABLE**Part I—Purposes**

- (a) Demonstration.
- (b) Advertisement.
- (c) Road test or endurance test on long and different terrain.
- (d) Test ground.
- (e) Export.

Part II—Conditions

1. The transport vehicle used for the purposes specified in items (a) and (b) of Part I shall display a letter specifying the route to be covered by such vehicle, the places at which the demonstration or advertisement, as the case may be, is to be held and the period for stay at each such place.

2. A vehicle used for a purpose, other than the purposes specified in items (a) and (b) of Part I shall:—

- (i) display a letter indicating the purpose for which the vehicle is being used and the place or places to which it is proceeding;
- (ii) display a trade certificate in accordance with the procedure prescribed in the Motor Vehicles Rules in force in the State;
- (iii) not carry any goods other than tools and accessories or any passengers other than a driver, one mechanic and two attendants and every such driver, mechanic and attendants shall possess identity cards or letters issued by a person who manufactures or deals in motor vehicles or builds bodies for attachment to chassis.

[No. 39-TAG(12)/70-I]

N. A. A. NARAYANAN, Under Secy.

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय**(श्रम और रोजगार विभाग)****आवज्ञा**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1973

का. आ. 1503.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसका उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नेशनल अंगरपाथरा कॉलियरी, डाकघर, कतरासगढ़, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

“क्या नेशनल अंगरपाथरा कॉलियरी, डाकघर कतरासगढ़, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, कठार कोक भट्टा की श्रीमती लक्ष्म्या कामिन को 9 अगस्त, 1972 से काम से रोकने को कार्रवाई न्यायचित है? यदि नहीं, तो सम्बंधित कर्मचार किस अनुतोष का हक्कार है?”

[संख्या एल.-2012(162)/72-एल आर-2]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION**(Department of Labour and Employment)****ORDER**

New Delhi, the 29th March, 1973

S.O. 1503.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of National Angarpathra Colliery Post Office, Katrasgarh, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And Whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of National Angarpathra Colliery, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad, in stopping Shrimati Laxmia Kamin of Hard Coke Bhatta from work with effect from the 9th August, 1972 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

[No. L-2012(162)/72-LRII]

New Delhi, the 16th May, 1973.

S.O. 1504.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th May, 1973.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI.

New Delhi, 1st May, 1973.

CG. Reference I. D. No. 2 of 1972.

Present :

Shri R. K. Baweja, Central Govt. Industrial Tribunal, Delhi.

BETWEEN

The employers in relation to the State Bank of India.

AND

Their workmen.

Shri A. R. Lall—for the management/bank.

Shri N. C. Sikri—for the workmen/Association.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, by S.O. No. L. 12012/123/71-LR/III dated 18th April, 1972 referred the following industrial dispute existing between the aforesaid parties for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of State Bank of India in terminating the services of Shri S. M. Gupta, Clerk of their Hauz Khas Branch, New Delhi with effect from the 10th of August, 1971 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. After the receipt of the order of reference, usual notices were issued to the parties and in pursuance thereof, the union filed a statement of claim on 25-5-1972. The management presented its written statement in reply thereto on 12-7-1972, and a rejoinder was also filed by the union in reply to the pleas raised in the written statement. The management denied that the workman was entitled to any relief and further pleaded that the union was not authorised to represent the workman and that it had no locus standi to espouse his cause. On the above pleadings of the parties, the following issues were framed :—

- (1) Whether the State Bank of India Employees Association is authorised to represent the workman?
- (2) Whether the union has the locus standi to espouse the cause of the workman? If not, its effect?
- (3) As in the term of reference.

Issues No. 1 & 2 :

3 There are two unions operating in the Bank. One is the State Bank of India Employees Association (hereinafter to be referred as the minority union) and the other is the State Bank of India Staff Association (hereinafter to be called the majority union). It is the minority union which has taken up the cause of the workman. Shri K. N. Malhotra, general secretary of the minority union appeared as a witness and deposed that the concerned workman Shri Gupta became the member of his union in 1970. He was employed in the Hauz Khas branch of the Bank where this union had 11 members out of 22 employees posted in the branch. In cross-examination the witness deposed that the total number of employees in Delhi circle was about 9,500 and out of them 4,600 were the members of his union. He brought the list of members of his union in support of his claim. By a letter dated the 17th of August, 1971 addressed

to the general secretary of the minority union Shri Gupta brought to its notice that his services had been illegally terminated by the management and requested the minority union to take up his cause. A copy of that letter is Ext. W/1 and it has been duly proved by the general secretary. On receipt of this letter, the union wrote a letter to the Agent, Hauz Khas branch of the Bank on the 27th of August, 1971 a copy of which is Ext. W/2. In this document, the management was called upon to reinstate Shri Gupta. On the 20th of October, 1971 the central committee of this union passed a resolution in which it decided that the cause of Shri Gupta be taken up by the general secretary vide Ext. W/3. Thereafter, Shri Malhotra addressed a letter to the Assistant Labour Commissioner on the 30th of October, 1971 in which it was brought to his notice that he should advise the bank to reinstate Shri Gupta and pay him his back wages. Then discussions between the minority union and the management took place before the conciliation officer of which the copies are Exts. W/5 to W/8. From this documentary evidence coupled with the statement of Shri Malhotra it is obvious that the minority union has on its roll a considerable number of employees of the management and 11 employees of the Hauz Khas branch where the workman was posted before his services were terminated were its members out of 22. No evidence in rebuttal was produced and I am, therefore, satisfied that the workman requested this union of which he was the member to take up his cause and the union then after passing a resolution in its executive committee meeting moved the conciliation officer and on the failure of the conciliation efforts the Government made the reference for adjudication to this Tribunal. I, therefore, decide both these issues in favour of the workman/union.

Issue No. 3 (Term of Reference) :

4. I shall like to mention several facts which led to the appointment of Shri Gupta as a clerk in the Hauz Khas branch of the Bank. By a letter dated the 29th of January, 1970 the Agent of that branch Shri H. L. Verma MW/1 brought to the notice of the Secretary and Treasurer at the head office of the bank in New Delhi that on account of the increase and pressure of work, sanction be accorded to appoint two temporary clerks as an interim measure. He stated that there were only five clerks who had been working in the bank, that it was very difficult to cope with the volume of work in the branch and that if posting of two temporary clerks was not made, the work of the branch would be in arrears. The head office by its letter dated the 7th of February 1970 Ext. M/2 informed the Agent that he should submit his recommendations regarding augmentation of clerical staff at his branch in the annual review of staff position for the year 1970 and in the mean time to complete the sanctioned strength of clerical staff at the branch, one Shri K. L. Arora, typist-clerk had been transferred from Panipat to that branch. It seems that Shri K. L. Arora did not report for duty to the Hauz Khas branch and so, the Agent Shri H. R. Sethi MW3 sent another letter dated the 18th of February 1970 to the head office in which the difficulty which was experienced by the branch was brought to its notice and it was requested that the sanction to appoint a temporary clerk-typist be accorded vide Ext. M/14. By a letter dated 26th February, 1970 Ext. M/3 the head office permitted the agent to appoint a temporary typist clerk at his branch for a period of one month on the usual terms and conditions under advise to the head office on proforma 'A' attached to the circular letter dated 29th July, 1969 vide Ext. M/3. It is, therefore, obvious from these letters which I have no doubt to suspect that the Agent got the sanction to appoint a temporary clerk in the branch on account of rush of work for a period of one month from the 27th of February, 1970. So, a letter of appointment was issued to the workman in which he was informed that he was appointed a temporary clerk in the branch for a period of one month and that his services would be treated as dispensed with on the 26th of March, 1970 unless the period was further extended vide Ext. M/4. Thereafter, his period was extended from month of month by letters Exts. W/24 to W/30. In the last letter dated 26th October, 1970 Ext. W/30 it was stated that Shri Gupta, a temporary clerk, should continue for a further period of one month with effect from the 27th of October, 1970 and that his services at the expiry of the aforesaid period would be treated as dispensed with unless they were further extended by the Bank. Shri Gupta, however, continued thereafter but there is nothing on the file to show if any such letters referred to above were issued to him extending his period from month to month after the 26th of November, 1970. The

next letter in this connection is dated the 11th of June, 1971 in which Shri Gupta was informed that he had been appointed as a temporary clerk for a period of one month from the 11th of June, 1971 and his services at the expiry of the aforesaid period would be treated as dispensed with unless the period was further extended. This letter was received by Shri Gupta on the 21st of June, 1971 vide Ext. M/11. Shri Gupta received this letter and signed as a token of its receipt while dating it as 21-6-1971. He then scored off the date and according to him it was at the instance of the Agent. Be that as it may the fact remains that the letter dated the 11th of June, 1971 was received by him on the 21st of June, 1971. Again by another letter dated 10th July, 1971 he was informed that his period had been further extended upto the end of July, 1971 and this letter was delivered to him on the 31st of July, 1971 vide Ext. M/12. By a previous letter dated the 7th July, 1971 the then Agent of the branch Shri S. N. Kathuria had recommended to the head office that the temporary service of Shri Gupta be extended for a further period of one month with effect from the 11th of July, 1971 and it was in pursuance of that letter that on its receipt the services of Shri Gupta were extended. On the 4th of August, 1971 the Dy. Secretary and Treasurer of the Bank informed the Agent of the Hauz Khas branch by a letter Ext. M/10 that in view of his recommendations contained in his letter dated the 7th of July, 1971 the services of Shri Gupta were extended upto 10th of August, 1971. On the 9th of August, 1971 the letter Ext. W/1 was issued by the Agent in which Shri Gupta was informed that his term would not be extended beyond the 10th of August, 1971 and his services would be treated as dispensed with vide Ext. W/11. This letter was acknowledged by Shri Gupta in his letter of the same date in which he protested against the allegedly illegal action of the management vide Ext. W/12. The Association has placed on record various representations and resolutions which were passed by it and in which the removal of Shri Gupta was assailed on various grounds. The Bank, however, in its letter dated the 16th of September, 1971 Ext. M/15 informed the workman that as he was a temporary clerk on purely temporary basis, his services were properly terminated and it was further added that the temporary appointment did not confer any right or claim for absorption in the permanent service of the Bank. He was further informed that all permanent appointments were made on the basis of a written test and interview and as he had failed to qualify in the test his services had been terminated.

5. The facts from the date of his appointment as a temporary clerk in the branch ending in his removal on the 10th of August, 1971 have been sufficiently narrated above. On behalf of the workman it was vehemently contended by his learned lawyer that by his continuing for more than one year, he had become a permanent employee and so, he could not be removed by the Bank in a summary manner. The various documents referred to above clearly indicate that he was appointed on temporary basis and his term was extended from month to month. The letters of the Bank extending his term on month to month basis upto the 26th of November, 1970 are there. No document was produced by the Bank to show as to in what capacity he was discharging his duties after the 26th of November, 1970 till the 11th of June, 1971 when by a letter Ext. W/11 Shri Gupta was informed that his term had been extended by another month and that he had been appointed in a temporary capacity. This was followed by another letter extending his term upto the end of July and then to the 10th of August, 1971. The question for determination is if under these circumstances can it be said that Shri Gupta had become a permanent incumbent in the service of the Bank? Shri Gupta when he appeared before me as WW2 admitted that in November, 1970 a test was held of candidates including himself. It seems that the workman failed in that test and for that reason he was not called for interview. Only those candidates were called for interview by the Bank who qualified in the test. Shri Gupta, however, did not admit that he failed in the test and said that as he was not informed that he had failed or passed in the test he presumed that he had passed. When asked as to how under these circumstances he could say that he had become permanent employee of the Bank he replied that Shri S. P. Saxena the Agent of the Bank told him that he had been declared a successful candidate and, therefore, he had become a permanent employee. The Bank produced Shri Rajinder Kumar, administrative officer at the head office of the Bank at New Delhi. He deposed that the note dated 28th July, 1971

Ext. M/9 bore his initials and the note marked 'A' in the margin was in the hand of Shri R. L. Mohinderoo who was the then staff superintendent. There it was mentioned that Shri Gupta who appeared in the test could not qualify and as the Agent had requested to the head office to allow him to continue for a further period of one month it may be done so. The staff superintendent in his marginal note noted that as Shri Gupta had not qualified in the test, his services should be positively terminated. Shri Saxena who, it was alleged by the workman, had told him that he had been confirmed as he was successful in the examination was not produced. Even upto the date of termination of his services the workman had never made a representation that he had been declared successful in the examination and for that reason he should be declared to be a permanent incumbent. Shri K. N. Malhotra, general secretary of the Association in his statement stated that the result was put up on the notice board in February, 1971. When asked if he found the name of Shri Gupta in that list he said that he could not say. He, however, admitted that Shri Gupta did not tell him that his name was on the list of successful candidates. The Association alleged that a second list of successful candidates was also put up on the notice board in June, 1971 but Shri Gupta did not inform the general secretary that he had been declared successful. He has also not produced any letter of the Bank showing that he received information that he had qualified in the test. This being so, it is very difficult to accept the statement of Shri Gupta that he had become permanent as the then Agent of the bank orally informed him that he had been declared successful in the test held by the Bank for the recruitment of clerks and that he had been confirmed. Even in June, 1971 when his term was extended for another month he did not protest that he was being described as a temporary clerk in the letter of extension though he had passed the examination and had been confirmed. I am, therefore, disposed to hold that Shri Gupta was a temporary hand and was not confirmed by the Bank.

6. The next contention of Shri Sikri was that if a bank employee put in more than one year of continuous service then under the various bank awards he acquired the status of a permanent hand. Para. 508 of the Sastry Award gives the classification of employees. The employees were classified as (a) permanent employees; (b) probationers; (c) temporary employees and (d) part-time employees. Permanent employee means an employee who has been appointed as such by the Bank. The workman was never appointed as a permanent employee. He was not a probationer because probationer means an employee who is provisionally employed to fill a permanent vacancy or post and has not been made permanent or confirmed in service. The various orders placed on the record by the Bank indicate that he was never appointed in a permanent vacancy and rather his appointment was for a specific period which was extended from time to time as the Bank was short of permanent hands and the work had increased. He comes within the definition of a temporary employee as given in clause (c) above. I was not referred to any para. of the Sastry or the Desai Award to this effect that by putting in a continuous service of more than a year a temporary employee could automatically become a permanent incumbent. I am, therefore, inclined to take the view that this submission of Shri Sikri was not well-founded when he argued that the workman should be deemed to have become permanent in view of the fact that his services were continuous or that there were permanent vacancies in the Hauz Khas branch of the Bank, against which he should be deemed to have been appointed.

7. It was next contended on behalf of the workman that if he was not a permanent hand even then the order terminating his services was not legal as he had put in more than one year's continuous service and as such he was entitled to retrenchment compensation under the relevant provisions of the Industrial Disputes Act and as it had not been done, the order was illegal. I have gone through the statement of claim filed on behalf of the workman by the Association. Nowhere in it, it was alleged that the order terminating the services of the workman was that of retrenchment and that while retrenching him the provisions of Section 25F were not followed. If a certain allegation has not been made in the pleadings then the parties are debarred from raising that plea during the course of arguments. Had it been so pleaded, the management would have met that

plea and a finding on that could be given. As no allegation of illegal retrenchment was made, I am afraid that Shri Sikri cannot be permitted to submit arguments on that point.

8. The other allegations in the statement of claim were that the workman had been victimised and had been discriminated. It was alleged that he made demands for payment of four days wages for the 23rd and 24th of April and 9th and 10th of June, 1971 against the illegal deductions for those days as he worked in the Bank during that period. He continued that when he demanded and protested against the deprivation of his claim as also his claim for over time allowance, the management victimised him by terminating his services. The allegations of discrimination as given in the statement of claim were that even the candidates who failed in the written test were called for interview at the instance of the majority union but he was denied that opportunity and that though he was a senior most employee in that branch, yet other similarly placed employees who were junior to him were continued in employment. He further added that even after the termination of his services, new recruits in the clerical cadre were taken but he was denied the opportunity of re-employment and those candidates who could not qualify in the written test were continued to be in its employment. So, these allegations of victimisation and discrimination are to be examined in the light of the evidence adduced by the parties.

9. Shri Gupta deposed before me that he did work on the 23rd and 24th of April, 1971 but the management showed a break in his service and deducted two days wages from his salary bill of April, 1971. The management admitted that such deductions were made but it was stated that it was due to the fact that Shri Gupta was absent on those two days. The overtime register, the draft mail advice register indicated that on those two days Shri Gupta made entries in them. Entries in the short collection payment register, the Daily Advice Register were also posted by Shri Gupta. Overtime allowance was also paid to Shri Gupta for having worked for five hours in excess of the prescribed hours on the 24th of April, 1971. Shri H. L. Verma the then branch manager in his cross-examination admitted that in the overtime register on page 73 the workman had been shown as having worked overtime for five hours on the 24th of April, 1971 and that he was paid overtime allowance for the whole month including the 24th of April, 1971. Shri Lall when confronted with this situation had nothing to say but added that the workman in collusion with the head clerk of the branch who was an office bearer of the minority union got these entries made. This explanation is hardly satisfactory. My attention was also drawn to the pay-sheets for the month of May, 1971 in which it was shown that deductions for two days were made from the salary of Shri Gupta for April, 1971. It was suggested that this pay-sheet was prepared by Shri Gupta and if really he had worked on those days how could he show therein that he was absent for that period. Shri Gupta, however, denied that the pay-sheet was prepared by him. Apart from the pay-sheet, the fact, however, stands established that Shri Gupta made entries in the various registers of the Bank on the 23rd and 24th of April, 1971 and was also paid overtime for five hours for putting in overtime work on the 24th of April, 1971. In my view this conclusively establishes that Shri Gupta worked on those days. I do not know why the Bank marked him absent for the 23rd and 24th of April, 1971. May be that it wanted to show a break in his service so that he may not claim any benefit, if any, of continuous service of more than one year. It is rather sad that a Bank of the status of the State Bank of India should have resorted to such mal-practice when it should act as a guide being the leading bank in the banking industry and to set an example for clean administration for the other Banks. Similarly, on the 9th and 10th of June, 1971 the workman stated that he applied for leave which he was told had been sanctioned but he was marked absent and his wages were deducted from his salary for those two days. On the 21st of July, 1971 it was brought by Shri Gupta to the notice of the management that he had worked for the entire month during April, 1971 but his wages had been deducted. A copy of that letter is Ext. W/1 and the postal receipt showing that this letter was sent by registered post is Ext. W/18. On the 14th of July, 1971 he had also sent a letter a copy of which is Ext. W/9 in which it was brought to its notice that he had applied for two days sick leave on the 8th of June, 1971 from 9-6-1971 to 10-6-1971 but he had come to know that his leave had

not been sanctioned with the result that he had not received his salary. The Bank, however, states that it did not receive any such application and so, he was marked absent for these two days. It is possible that after the receipt of the application, the Bank might not have sanctioned the leave resulting in the deductions of his wages for the 9th and 10th of June, 1971. The question that is to be decided is, whether on account of these representations was the Bank annoyed to such an extent that it terminated the services of the workman? I do not think that any such inference can be drawn. There is nothing on the record to suggest that he was an active member of the Association and that on account of those activities the Bank was unhappy with him. The mere fact that he made representations for his two days salary for 9th and 10th of June, 1971 cannot indicate that this was the motive for the Bank to dispense with his services and that he was victimised on that score.

10. The next submission made on behalf of the workman was that temporary hands which were recruited by the Bank and had been posted at the Hauz Khas branch were continued in service after the 10th of August, 1971 when he was asked to quit. According to the workman he was senior to them and should have been continued and if there was any reduction in work the junior hands should have been asked to go. In this connection, instances of two workmen, namely, Miss Sushila Malkhani and Miss Monishadher were cited. A statement was also placed on the record and it showed that Miss Malkhani was recruited on the 15th of May, 1971 and continued upto the 16th of August, 1971. Miss Dhar joined the Bank in temporary capacity on the 16th of May, 1971 and the statement which was filed by the workman showed that she was continued upto the 16th of June, 1971 when it was alleged that she was transferred from the Hauz Khas branch to the New Delhi Local Head Office. In order to satisfy myself if the workman was discriminated on the above facts I adjourned the case for ascertaining the truth as to why it was done. The Bank produced the necessary papers and the record with regard to the appointment of these two employees as temporary clerks in the service of the Bank. Admittedly they were junior to Shri Gupta because he was appointed on the 26th of February, 1970. The correspondence placed on the record by the Bank indicates that on the 14th of April, 1971 Shri P. N. Saxena, Agent of the Hauz Khas branch wrote to the local head office that on account of the fact that certain clerks were on leave, it was necessary to appoint at least one temporary clerk for a period of fifteen days to ensure smooth and efficient running of the branch. The local head office by its letter dated the 22nd of April, 1971 replied that it had no objection to this request for the appointment of a temporary clerk for fifteen days in the first instance provided he was out of the candidates who had qualified in the recent clerical test held by that office. It is to be noted that Miss Malkhani had qualified in the test held in November, 1970 in which Shri Gupta had failed. The bank manager in his letter dated the 17th of May, 1971 informed the staff section of the local head office that Miss Malkhani had been appointed as a temporary clerk for fifteen days as she had qualified in the clerical test. Miss Malkhani's term then continued to be extended from month to month as in the case of Shri Gupta. On the 10th of August, 1971 she was issued a letter of appointment as a permanent hand since she had qualified in the test. On the 19th of August, she was appointed as a typist clerk on six months probation on the usual terms and conditions. It is, therefore, obvious from the above discussion that on account of the increase in work in the Hauz Khas branch due to the proceeding on leave of several employees, the necessity of an additional temporary hand was felt. The local head office imposed the condition that he/she should be out of the qualified candidates. She continued as a temporary clerk on month to month basis till the 10th of August, 1971 when she was offered that post on permanent basis. So, her case is quite distinguishable from that of Shri Gupta who had not qualified and was a temporary hand on various extensions.

11. The next case was that of Miss Dhar. By a letter dated the 2nd of April, 1971 the head office informed the Agent of the Hauz Khas branch that on account of the up-grading of Malviya Nagar Sub-office to a fullfledged branch, he was permitted to appoint a temporary clerk for a period of one month on usual terms and conditions under advice to it but it was pointed out that such a appointee should be out of the successful candidates in the test held at the head office. The agent by his letter dated the 17th of May, 1971 appointed Miss Dhar as a temporary clerk for a period

of one month from the 17th of May, 1971 and she was informed that her services at the expiry of the aforesaid period would be treated as dispensed with. On the same day, the agent informed the local head office that Miss Dhar was out of the successful candidates and had been appointed as a temporary clerk. Her term was extended further and she continued till the 10th of August, 1971, when she was informed that she had been taken on regular basis on account of her having passed the test. So, her case, too, was at par with the case of Miss Malkhani and it cannot be said that the workman was discriminated vis-a-vis this incumbent. Had the concerned workman qualified in the test and had his service been terminated on the 10th of August, 1971 while the above two employees had been retained in service, it could be said that he was discriminated. But as he had failed in the test, he could not be placed at par with the above two ladies.

12. Two other persons, namely, Shamli Kundra and Miss Saroj Kumari were appointed on the 25th of October, 1971 and 19th of November, 1971 respectively. It was done long after the services of the workman had been terminated. It was not a case of retrenchment and so the workman was not entitled to the benefit of Section 25H of the Industrial Disputes Act. The Bank was, therefore, not bound to offer him new appointment if it wanted to have new hands on temporary basis in the same branch. I have discussed the cases of these four employees above as were pointed out in the rejoinder filed by the Association. Shri Malhotra, however, made a statement that the persons mentioned in the list Ext. W/31 though they had failed to qualify the test, were retained in service as temporary hands and were given another chance to qualify in the test in March, 1972. In cross-examination, however, he admitted that he did not know if there were any temporary employees of his Association who were senior to them and whose services were terminated. He also admitted that he did not remember if he received any complaint from temporary employees who were members of his Association and whose services were terminated. Then he continued that temporary employees were not members of his Association. He that as it may, it has not been established by the Association whether these employees mentioned in Ext. W/31 had failed in the test and were retained in the various branches of the Bank and under what circumstances. The Association should have sent for the record of each employee in order to satisfy this Tribunal that they had been retained in spite of the fact that they had failed in the examination when there was nothing to justify their retention. In the absence of any such evidence I cannot impute any malafide motive to the management.

13. The upshot of the above discussion is that the Association has not succeeded in proving that Shri Gupta was a permanent hand, that his services were terminated on account of any malafides and that he had been discriminated because he was a member of the minority Association. In my view, therefore, he is not entitled to any relief in these proceedings and the reference is answered in favour of the management. The award is made accordingly. (Fifteen pages)

1st May, 1973.

R. K. BAWEJA, Presiding Officer.

[No. L. 12012/123/71/LRIII]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मई, 1973

क्र. आ. 1505.—डॉक कर्मक्षेत्र (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उपधाराओं (2) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा श्री आर श्रीनिवासन के स्थान पर श्री बी. के. राव को 7 मई, 1973 के पूर्वाह्न से भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2692 दिनांक 30 नवम्बर, 1959 द्वारा स्थापित विशाखापत्तनम डॉक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं और उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नीलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) पैराग्राफ 1 में, “केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले” शीर्ष के नीचे, मद्द (1) के लिए, निम्नीलिखित मद्द प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1) श्री बी. के. राव, अध्यक्ष,

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास,

विशाखापत्तनम ;”

(2) पैराग्राफ 2 के लिए, निम्नीलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2. केंद्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी. के. राव, अध्यक्ष, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती हैं।”

[संख्या बी. 15012/1/73-पी एण्ड डी]

वी. शंकरलिंगम, अवर सीक्रेटरी

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या बी. 15012/1/73-पी. एण्ड डी. दिनांक 11 मई, 1972 के साथ संलग्न किया जाने वाला प्वाल्पात्मक द्वापन

श्री आर. श्रीनिवासन ने 7 मई, 1973 के पूर्वाह्न से विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ दिया और श्री बी. के. राव ने उनसे अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभाल लिया। विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के अध्यक्ष की हस्तियत में, श्री बी. के. राव को 7 मई, 1973 के पूर्वाह्न से विशाखापत्तनम डॉक श्रम बोर्ड, विशाखापत्तनम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। श्री बी. के. राव की इस प्रकार की भूतलक्षी प्रभाव से नियुक्त करने के फलस्वरूप किसी तीसरे व्यक्ति के हित को कोई हानि नहीं पहुँचेगी।

New Delhi, the 11th May, 1973

S.O. 1505.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri B. K. Rao, as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board established under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2692 dated the 30th November, 1959, with effect from the forenoon of the 7th May, 1973, vice Sh. R. Srinivasan and makes the following further amendments in the said notification, namely :—

In the said notification.—

(1) in paragraph 1, under the heading “Members representing the Central Government”, for item (1), the following item shall be substituted, namely :—

“(1) Shri B. K. Rao, Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.”

(2) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“(2) The Central Government hereby nominates Shri B. K. Rao, Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, Chairman of the said Board.”

[No. V. 15012/1/73-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

Explanatory Memorandum to be appended to the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Notification No. V. 15012/1/73-P&D dated 11-5-1973

Shri R. Srinivasan relinquished charge of the post of Chairman, Visakhapatnam Port Trust on the forenoon of 7th May, 1973 and Shri B. K. Rao, took over charge of the post of Chairman from him. In his capacity as the Chairman of the Visakhapatnam Port Trust, Shri B. K. Rao is being appointed as the Chairman, Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam with effect from the forenoon of 7th May, 1973. No third person's interest would be adversely affected by giving such retrospective effect to the appointment of Shri B. K. Rao.

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 1973

का. आ. 1506.—यतः मैसूर लोह और इस्पात लि., भद्रावती, जिला शिमोगा, मैसूर राज्य के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व मैसूर लोह और इस्पात लि. खान कर्मचारी संघ करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और कर्मचारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थता करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थता करार को, जो उसे 14 मई, 1973 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 क के अधीन) के बीच पक्षकारों के नामः श्री चिके उर्स,

नियोजकों का प्रतिनिधित्व प्रभागीय प्रबंधक कार्मिक मैसूर लोह और इस्पात लि., भद्रावती, शिमोगा जिला मैसूर राज्य

कर्मचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले. श्री अश्वल खुद्स अन्वर, अध्यक्ष, मैसूर लोह और इस्पात लि. खान कर्मचारी संघ, भद्रावती, शिमोगा जिला ।

पक्षकारों के बीच निम्नीलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एम. आर. राजू, प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद के माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का करार किया गया है :—

1 विनिर्दिष्ट विवाद-ग्रस्त विषय क्या मैसूर लोह और इस्पात लि. भद्रावती के प्रबन्धतंत्र की मैसूर लोह इस्पात लि., भद्रावती की केमानसूडी खानों के सहायक रसोईया, श्री एम. एस. नारायण राव, की सेवाओं की 11 अगस्त, 1971 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुत्पी का हकदार है ।

2- विवाद के पक्षकारों का विवरण, (1) महाप्रबंधक मैसूर लोह और इस्पात लि., भद्रावती, का नाम और पता भी सम्मिलित शिमोगा जिला है । और

(2) उनका कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष, मैसूर लोह इस्पात लि. खान कर्मचारी संघ भद्रावती करते है ।

3- प्रभावित उपक्रम में नियोजित

कर्मचारों की कुल संख्या लगभग 500

4- विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्य. 1 (एक)

प्रभावित होने वाले कर्मचारों को

प्राक्कलित संख्या

हम यह करार भी करते हैं कि माध्यस्थता का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा ।

माध्यस्थ अपना पंचाट भारत सरकार द्वारा इस कगार को सरकारी राज-पत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थता के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले	कर्मकार प्रतिनिधित्व करने वाले
ह. (एच. चिके उर्स)	ह. (अश्वल खुद्स अन्वर
प्रभागीय प्रबंधक (कार्मिक)	अध्यक्ष, मैसूर लोह इस्पात
मैसूर लोह और इस्पात लि.,	लि. खान कर्मचारी संघ,
भद्रावती ।	भद्रावती ।

साक्षी:-

ह. (1) एच. एन. गामा राव,
महा सचिव, मैसूर लोह
और इस्पात लि. खान
कर्मचारी संघ, भद्रावती ।

ह. (2) एम. सेल्वारजन, सचिव,
मैसूर लोह और इस्पात लि.
खान कर्मचारी संघ, भद्रावती
बंगलौर

दिनांक 24 अप्रैल, 1973

[संख्या एल-29012/17/73-एल. आर.-4]

एस. एस. सहस्रनामन, अवर सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1973

S.O. 1506.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Mysore Iron and Steel Limited, Bhadravati, District Shimoga, Mysore State and their workmen represented by Mysore Iron and Steel Limited Mines Employees' Association;

And whereas the said company and the Union have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 4th May, 1973.

(Agreement)

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947).

BETWEEN

Name of the Parties :

Representing employers :

Shri CHIKKE URS, Divisional Manager (Personnel),
Mysore Iron & Steel Limited, Bhadravati, Shimoga
District, Mysore State.

Representing the workmen :

Shri ABDUL KHUDDUS ANWAR, President, Mysore
Iron & Steel Limited Mines Employees' Association,
Bhadravati, Shimoga District.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri M. R. Raju, Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad.

(i) Specific matters in the dispute :

"Whether the action of the management of Mysore Iron & Steel Ltd., Bhadravati, in terminating the services of Shri M. S. Narayana Rao, Asstt. Cook, Kemmangundi Mines of MISL, Bhadravati, with-effect from 11th August, 1972, is justified? If not what relief the workman is entitled to?

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and addresses of the establishment or undertaking involved :

(1) The General Manager, Mysore Iron & Steel Limited, Bhadravati, Shimoga District; and

(2) Their workman represented by the President, Mysore Iron & Steel Limited Mines Employees' Association, Bhadravati.

(iii) Total number of workmen employed in the undertaking :

About 500.

(iv) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute :

1 (One)

We further agree that the decision of the Arbitrator will be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 3 months from the date on which this agreement is published by Government of India in the official gazette, or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made

within the period aforementioned the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Representing the employer :

H. CHIKKE URS, Divisional Manager
(Personnel) Mysore Iron & Steel Ltd.,

Representing the workman:

ABDUL KHUDDUS ANWAR, President,
Bhadravati.

MISL Mines Employees' Association,
Bhadravati.

Witnesses :—

(1) H. N. SHAMA RAO, General Secretary, Mysore Iron & Steel Limited Mines Employees' Association, Bhadravati.

(2) M. SELVARAJAN, Secretary, Mysore Iron & Steel Limited Mines Employees' Association, Bhadravati.

Bangalore

Dated 24th April, 1973.

[No. L-29012/17/73-LR. IV]

New Delhi, 16th May, 1973.

S.O. 1507.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Associated Cement Companies Ltd., Jamul Cement Works, District Durg (Madhya Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th May, 1973.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CUM LABOUR COURT, JABALPUR

Jabalpur, April 9, 1973

Present :

Mr. Justice S. N. Katju, Presiding Officer.

Case No. CGIT/(LC)(R)(45) of 1972

(Notification No. L-29011(37)/72-LRIV dated 21-11-1972)

Parties :

Employers in relation to the management of Associated Cement Companies Limited, Jamul Cement Works Lime Stone Quarries, Post Office Jamul Works District Durg (Madhya Pradesh) and their workmen represented by Sanyukta Khadan Mazdoor Sangh, Jamul Quarry Branch, Nandini Road, Bhilai, District Durg (Madhya Pradesh).

Appearances :

For employers—Sri P. S. Nair.

For workman—none.

Industry : Lime Stone Quarry.

District : Durg (M.P.).

AWARD

This is a reference under Sec. 10(2) of the Industrial Disputes Act (Hereinafter referred to as the Act).

The two questions referred to this Tribunal for its adjudication are as follows :

(1) Whether the demand of the workmen for payment of bonus @ 20 per cent of their basic salary/wages and D.A. for the accounting year 1970-71 is justified under the provisions of the Payment of Bonus Act? If not, to what quantum of bonus should be paid to them for the said accounting year 1970-71 under the said Act?

- (2) Whether the demand of the workmen employed in the Quarries for payment of Night Shift Allowance is justified? If so, to what relief are the concerned workmen entitled?

The Sanyukta Khadan Mazdoor Sangh (hereinafter called the Sangh) has raised the demand on behalf of the workers of the Jamul Cement Works Limestone Quarries which is under the management of Associated Cement Companies Limited for payment of maximum Bonus i.e. 20 per cent of basic/salary/wages and D.A. for the accounting year 1970-71 on the ground that the Company earned huge profits in that accounting year in relation to its establishment at Jamul. It was contended that the allocable surplus far exceeded the amount of minimum bonus payable to the employees under Sec. 10 of the Payment of Bonus Act, 1965 and therefore the claim for payment of bonus at the aforesaid rate of 20 per cent was justified and reasonable. It was alleged that the Company had paid bonus for the accounting year 1970-71 at the rate of 4 per cent only. It had been informed by the management that the Associated Cement Companies had incurred loss in the accounting year 1970-71 and therefore the claim for bonus at the rate of 20 per cent was not justified. The Sangh also made a demand for wages for working in night shifts at the rate of "minimum 9 hours" pay for 8 hours working in night shift". The management in its reply has contended that the dispute between the Jamul Cement Works and its employees was settled as a package deal by two agreements both of which were entered into between the parties on 6-5-1971. The workmen in the aforesaid agreements were represented by the Cement Kamgar Sangh, Jamul and by the Chhattisgarh Cement Karamchari Sangh, Jamul. Under the terms of the aforesaid agreements the workmen had accepted bonus for the year 1969-70 and 1970-71 and for the accounting year 1971 the workmen were paid the statutory bonus of 4 per cent and an adhoc ex-gratia amount of 4 per cent. This comes to 8 per cent of the basic salary/wages and D.A. earned by the employees in the accounting year 1970-71. It was contended that although the Company incurred a loss of about 1.28 lacs, it, nevertheless, agreed to pay the workmen ex-gratia bonus at the rate of 4 per cent over and above the statutory bonus of 4 per cent. It was contended that after the aforesaid agreements the Sangh has again raised the present dispute for which it has no justification and that the aforesaid agreements were binding on the parties.

It was contended on behalf of the Company that the reference is not maintainable. I need not go into this question because on the material before me I am satisfied that the demands raised on behalf of the workmen by the Sangh are untenable. No one appeared on behalf of the workmen on 9-3-1972. A telegram was received on that date from the representative of the workmen praying for adjournment. Today was fixed for filing of rejoinders and final hearing of the case. No one has appeared on behalf of the workmen today. Ramji Singh was examined on behalf of the Company. He stated that the aforesaid two agreements were executed between the parties as mentioned in the said agreements and the terms of the agreements were fully implemented and the workmen were paid bonus, as agreed upon by the parties. It was further stated by Ramji Singh that the Company had incurred a loss of 1.28 lacs in the accounting year 1970-71. The Asso-

ciated Cement Companies ran about 15-17 undertakings and the Company had a single balance sheet and Profit and Loss Account which were made in respect of the operation of all the units of the Company. The Balance Sheet of the Company for the accounting year 1970-71 has been produced. There is nothing to substantiate the allegations made on behalf of the workmen that the Jamul Cement Works had made profits. Under these circumstances, I am not prepared to hold that the Sangh was justified in ignoring the aforesaid agreements between the parties which had been fully implemented by the Company.

There appears to be no force in the Sangh's contention that the workmen are entitled to extra payment for working in night shifts. It has been stated on behalf of the Company that the workmen work in rotation and there are three shifts including the night shift. Ramji Singh (E.W. 1) stated that there was no practice of paying extra wages to workmen for working in night shifts. He also gave instances of a disputes of a similar nature in certain other concerns in which Mr. Justice Das in his award, as also the Central Government Industrial Tribunal Bombay had expressed the view that the demand for payment of any extra wages for working in night shifts by the workmen was not justified.

My answer to the reference, therefore, is that the demand of the workmen for payment of bonus for the accounting year 1970-71 is not justified and further that the demand of the workmen employed in the Quarries for payment of Night Shift Allowance is also not justified. The workmen, therefore, are not entitled to any relief. I make my award accordingly. I make no order for costs.

S. N. KATJU, Presiding Officer.

[No. L-29011(37)/72-I.R. IV]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 मई, 1973

का. आ. 1508.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पीठल धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री ए. आर. पिल्ले, मुख्य श्रम और कल्याण अधिकारी, मँगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर और श्री प्रकाश राय कां, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और राजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 250, तारीख 19 जनवरी, 1973 द्वारा नियुक्त सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित करती हैं और निर्देश देती हैं कि उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:—

- (1) प्रारम्भिक पैरे में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके अधीन चलाये जाने वाले अनुसूचित नियोजनों की बाबत" शब्दों का लोप किया जाएगा,

- (2) नियोजकों के प्रतिनिधि से संबंधित मद् 2 में प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“6. श्री ए. आर. पिल्लै, मुख्य श्रम और कल्याण अधिकारी, मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड, 3, माउंट रोड, एक्सटेंशन, नागपुर”,

- (3) कर्मचारीयों के प्रतिनिधि से संबंधित मद् 3 में प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“6. श्री प्रकाश राय,
संयुक्त मदान मजदूर संघ,
चिकली, डाकघर राजनन्द गांव,
जिला दूर्ग (मध्य प्रदेश)।

[सं. एस-32023(1)/73-डब्ल्यू. ई. (एम. डब्ल्यू.)]

हंस राज छाबड़ा, अवसर सचिव।

New Delhi, the 16th May, 1973

S.O. 1508.—In exercise of the powers conferred by section 7, read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby nominates Shri A. R. Pillai, Chief Labour and Welfare Officer, Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur and Shri Prakash Roy to be as members on the Advisory Board appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 250 dated the 19th January, 1973 and directs that the following amendments shall be made in the said notification, namely :—

- (i) in the opening paragraph, the words “in respect of the scheduled employments carried on by or under the authority of the Central Government” shall be omitted;
- (ii) in item II relating to ‘Representatives of Employers’, after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—

“6. Shri A. R. Pillai,
Chief Labour and Welfare Officer,
Manganese Ore (India) Ltd.,
3, Mount Road Extension,
Nagpur.”;

- (iii) in item III relating to ‘Representatives of Employees’, after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—

“6. Shri Prakash Roy,
Samyukta Khadan Mazdoor Sangh,
Chikli P.O. Rajanandgaon,
District Durg (M.P.)”.

[No. S. 32023(1)/73-WE(MW)]
HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1973.

का. आ. 1509.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, न. व. सुन्दरामन, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा नगर विकास, लोक, स्वास्थ्य तथा आवास विभाग की अधिसूचना संख्या एच. एस.-1071-1(ए)(1) दिनांक 22 मार्च, 1973 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गेरे द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियां इस शर्त पर सौंपता हूँ कि उक्त उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त सौंपी गई उपर्युक्त शक्तियों के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में मुआवजा भंडार की ऐसी भूमि तथा सम्पत्तियां जिनका निपटान 1 अगस्त, 1971 से पहले नहीं किया गया था, को छोड़कर शेष भूमि तथा सम्पत्तियों के निपटारे के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

[संख्या 2(8)/विशेष सेल/89-एस. एस.-2]

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 7th May, 1973

S.O. 1509.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954, I, N. V. Sundararaman, Chief Settlement Commissioner hereby delegate to the Deputy Chief Settlement Commissioner appointed by the Government of Maharashtra under Urban Development, Public, Health and Housing Department Notification No. HS-1071-1(A) (1) dated the 22nd March, 1973, the powers exercisable by me under the said Act, subject to the condition that the said Deputy Chief Settlement Commissioner shall not under the aforesaid delegated powers take any steps for the disposal of lands and properties of the Compensation Pool within the State of Maharashtra except those that were not disposed of before the 1st August, 1971.

[No. 2(8)/Spl. Cell/69-SS. II]

का. आ. 1510.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, न. व. सुन्दरामन, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा नगर विकास, लोक, स्वास्थ्य तथा आवास विभाग की अधिसूचना संख्या एच. एस.-1071-1(ए)(1), दिनांक 3 मई, 1972 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए नियुक्त किए गए बन्दोबस्त आयुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 23 एवं 24

द्वारा या उसके अन्तर्गत मुझे सौंपी गई शक्तियां इस शर्त पर सौंपता हूँ कि उक्त बन्दोबस्त आयुक्त निम्नलिखित मामलों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे:—

- (क) मुआवजा भंडार की ऐसी सम्पत्तियां जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं हैं ;
- (ख) ऐसे मामले जिनके संबंध में उसके द्वारा क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त बम्बई की क्षमता में आदेश पागित किए जा चुके हैं; और
- (ग) क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त, बम्बई की क्षमता में उसके पूर्वाधिकारी के किसी आदेश में परिवर्तन ।

[संख्या 2(8)/विशेष सेल/69-एस. एस.-2]

न. व. सुन्दररामन, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

S.O. 1510.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954, I, N. V. Sundararaman,

Chief Settlement Commissioner hereby delegate to the Settlement Commissioner for Maharashtra State appointed by the Government of Maharashtra under Urban Development, Public Health and Housing Department Notification No. HS-1071-1(A) (1), dated the 3rd May, 1972 the powers conferred on me by or under Sections 23 & 24 of the said Act, subject to the condition that the said Settlement Commissioner shall not exercise any such powers in relation to the following :—

- (a) Compensation Pool properties not situated in Maharashtra State ;
- (b) Matters in which an order has been passed by him in his capacity as a Regional Settlement Commissioner, Bombay, and
- (c) Revision of any order of his predecessor in his capacity as Regional Settlement Commissioner, Bombay.

[No. 2(8)/Spl. Cell/69-SS. II]

N. V. SUNDARARAMAN,
Chief Settlement Commissioner